● वर्ष-2
● अंक-196
रायपुर, शनिवार
08 अप्रैल 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

कोरोना रफ्तार, 10-11 अप्रैल को मॉक ड्रिल

24 घंटे में 6050 केस आए

नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 6050 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। यह बीते दिन मिले नए केसों से करीब 13 फीसदी ज्यादा है। देश में कोरोना के सक्रिय केस यानी उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 28,303 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को देश में 195 दिन बाद कोरोना 5,335 नए मामले आए थे। पिछले साल 23 सितंबर को कोरोना के 5,383 दैनिक मामले सामने आए थे। देश में अब तक 4.47 कारोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।

भारत में 203 दिन बाद एक दिन में कोरोना के 6,050 नए मामले आए हैं। इससे पहले पिछले साल 16 सितंबर को संक्रमण के 6,298 दैनिक मामले सामने आए थे। देश में अब तक 4.47 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में तीन, कर्नाटक तथा राजस्थान में दो-दो और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में एक-एक मरीज की मौत हुई। देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5.30 लाख के पार पहुंच गई है। साथ ही संक्रमण से मौत की संशोधित सूची जारी करते हुए केरल ने एक नाम और जोड़ा है।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की और राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए तैयार रहने की सलाह दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख एवं अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ आभासी रूप से आयोजित बैठक में मंडाविया ने इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की निगरानी के द्वारा आपातकालीन हॉटस्पॉट की पहचान करने और परीक्षण एवं टीकाकरण में तेजी लाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का मॉक ड्रिल करने और आठ और नौ अप्रैल को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का भी आग्रह किया।

38.2 फीसदी मामले एक्सबीबी.1.16 वैरिएंट के

देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पता चला है कि सामने आ रहे नए मामलों में वायरस का एक्सबीबी.1.16 वैरिएंट सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अब तक कोविड-19 के जितने मामले सामने आए हैं, उनमें से 38.2 फीसदी इसी स्वरूप के हैं। भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक संगठन (आईएनएसएसीओजी) के नए बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। गुरुवार को जारी 27 मार्च के बुलेटिन में कहा गया कि मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह तक एकत्र किए गए नमूनों में से एक्सबीबी सबसे आम तौर पर प्रसारित होने वाला ओमिक्रॉन उपस्वरूप रहा है।

21 राज्य के 72 जिले रेड अलर्ट

बीते चार सप्ताह से देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के चलते 21 राज्य के 72 जिले रेड अलर्ट में आए हैं। इन जिलों में बीते सप्ताह के दौरान 12 से 100 फीसदी तक सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के सबसे अधिक जिले रेड अलर्ट में हैं। दिल्ली के 11 में से नौ जिलों में सबसे अधिक संक्रमण है, दिल्ली के एक छोर पर गुरुग्राम-फरीदाबाद तो वहीं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में एक समान स्थिति देखने को मिल रही है। इन तीनों जिलों में संक्रमण दर क्रमश: 12.84, 12.06 और 11.72 फीसदी है।

कोरोना के एक वैरिएंट एक्सबीबी.5 पर नजर

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगे सूचित किया गया कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना के एक वैरिएंट पर बारीकी से नजर रख रहा है। डब्ल्यूएचओ एक्सबीबी.5 और छह अन्य वेरिएंट की निगरानी कर रहा है। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जहां ओमिक्रॉन और इसकी उप-वंशावली प्रमुख वैरिएंट बनी हुई है, वहीं अधिकांश वैरिएंट में बहुत कम या कोई महत्वपूर्ण संप्रेषणीयता, रोग की गंभीरता या प्रतिरक्षा बचाव नहीं है। एक्सबीबी.5 का प्रचलन फरवरी में 21.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 35.8 प्रतिशत हो गया है।

टीकाकरण केंद्र तलाशते लोग

कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के चलते लोग बूस्टर डोज की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, भारत के प्रमुख शहरों में भी जिन निजी केंद्रों पर टीके उपलब्ध हैं, उनकी संख्या केवल गिनती भर रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के कोविन पोर्टल से पता चलता है कि मुंबई में लगभग सात टीकाकरण केंद्र संचालित हैं। इनमें से सिर्फ जेजे हॉस्पिटल ही नि:शुल्क या सरकारी केंद्र है। जबकि दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में 11 केंद्र संचालित हैं।

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगनीति 2022

छत्तीसढ़ में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगनीति लागू की गई है। इस नीति के तहत राज्य में 300 रूलर इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना की जा रही है। जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार की बनी है तब से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के नेताओं ने यही कल्पना की थी कि देश में लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से स्वदेशी अर्थ नीति लागू की जाएगी। किन्तु स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक नीति में ग्रामीण स्वालंबन कही गुम हो गया। यह अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई है। लेकिन केवल नीति बनाने से काम नहीं चलेगा। जो रीपा की स्थापना की बात हो रही है वह जमीनी स्तर पर अभी लागू नहीं हो पाया है। नीति में भी लघु और कुटीर उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में किस-किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा यह भी स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर जो लघु और सूक्ष्म उद्योग लगाने की योजना चल रही थी उसी का स्वरूप बदलकर उसे नया नाम दे देने से कोई लाभ नहीं होगा। जब से राज बना है तब से बड़े और मध्यम उद्योग लगाने हजारों लाखों करोड़ रूपए के समझौते किए गए, हालाकि राज्य बनने के बाद पूरे प्रदेशभर में उद्योग लगे है और यहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला है। लेकिन पिछले चार वर्षों से बड़े उद्योग लगाने की गति मंद हुई है। प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता देने की योजना भी शुरू हुई है। अब इन बेरोजगारों को उद्योगों में रोजगार मिल जाए तो युवाओं को अधिक खुशी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संस्थानों की कमी नहीं है। दूसरी ओर प्रदूषण फैलाने वाले लौह और कोयला अधारित उद्योंगों की संख्या में प्रदेश में बहुत प्रगति की है जबकि आईटी, सॉप्टवेयर और इलेक्ट्रानिक जैसे उद्योग लगाने में हम असफल रहे। बिजली और स्टील का भरपूर उत्पादन करने के बावजूद प्रदेश में मोटर गाड़िया और मशनीरी उद्योग भी स्थापित नहीं हो पाया। बस आंकड़ों के नाम प्रदेश में कितने उद्योग लगाने के समझौते हुए का ब्योरा दे दिया जाता है। वह आंकड़ा भी पता नहीं कहा से निकालकर लाया जाता है। ग्रामीण और कुटीर उद्योगनीति से संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश में पिछले चार वर्षों में 21000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ और 40 हजार लोगों को रोजगार मिला जबकि माहभर पहले विधानसभा में उद्योगमंत्री ने बताया था कि वर्तमान में 4261 करोड़ का निवेश हुआ है और 3256 लोगों को रोजगार मिला है। इस तरह की कलाबाजी से आर्थिक विकास नहीं होता, यह बात सही है कि प्रदेश में गरीबी दूर करने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की मजबूती जरूरी है इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं का रूझान उद्यम स्थापित करने की ओर जाएगा। किसी राज्य का विकास और पहचान उसके युवा की उद्यम शीलता से भी होती है। कुटीर उद्योग नीति पर सरकार गंभीर हो और इसे व्यवस्थित रूप से लागू करने से ही परिणाम आएंगे।

दक्षिण में हिंदू गुरुओं के सेवा कार्य मिशनरियों से अधिक: डॉ. भागवत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत ने कहा है कि दक्षिण के प्रांतों में हिंदू आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा किए गए सेवा कार्य मिशनरियों से कहीं अधिक हैं। वह जयपुर के जामडोली में केशव विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा भारती के सेवा संगम के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सेवा कहने के बाद सामान्यत: देश के प्रबुद्धजन मिशनरियों का नाम लेते हैं। दुनिया भर में मिशनरी अनेक स्कूल, अस्पताल चलाते हैं, यह सभी को पता है। लेकिन दक्षिण के प्रांतों में, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य मुनि,

संन्यासी सब मिलाकर जो सेवा करते हैं वह मिशनरियों की सेवा से कई गुणा ज्यादा है।'' भागवत ने कहा, ''मैं स्पर्धा की बात नहीं कर रहा। उनसे ज्यादा, उनसे कम, यह मेरा पैमाना नहीं है। सेवा का यह पैमाना हो ही नहीं सकता।'' उन्होंने कहा कि सेवा स्वस्थ समाज को बनाती है लेकिन स्वस्थ समाज को बनाने के लिए पहले वह पहले हमको स्वस्थ करती है। संघ प्रमुख ने कहा, ''सेवा मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।'' आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत ने पीछे रह गए वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने पर जोर देते हुए कहा कि समाज को सभी को समान मानकर इस पिछड़ेपन को दूर करना होगा। उन्होंने सेवा को मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी बताया। समाज में व्याप्त पिछड़ेपन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारे समाज का केवल एक अंग पीछे नहीं है बल्कि उसके कारण हम सब लोग पिछड़ गए हैं। हमें यह पिछड़ापन दूर करना है। हमें सभी को समान, अपने जैसा मानकर सेवा के माध्यम से उन्हें अपने जैसा बनाना है। हम इसके लिए संकल्प ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं।'' भागवत ने कहा, %%हम सभी मिलकर समाज हैं। यदि हम एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे। यदि सभी एक-दूसरे के साथ हैं तभी हम पूर्ण बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह विषमता आई है। हमको यह विषमता नहीं चाहिए।'' उन्होंने कहा, हम अपना-अपना काम करते होंगे। काम के अनुसार रूप-रंग भले ही निराला होता होगा। लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। समाज का एक अंग उपेक्षित हो- यह कैसे हो सकता है। यदि देश को विश्व गुरु बनाना है तो इसका मतलब है कि वह सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए।

प्रमुख समाचार

बैसाखी से पहले भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए 2,856 वीजा जारी

नई दिल्ली। बैसाखी के अवसर पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने सिख तीर्थयात्रियों को 2,856 वीजा जारी किए हैं, जो 9-18 अप्रैल 2023 तक पाकिस्तान में वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारत से यात्रा करेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने जानकारी दी कि उसने भारत के सिख तीर्थयात्रियों के लिए 2800 से अधिक वीजा जारी किए हैं, जिन्हें 12 अप्रैल से शुरू होने वाले पाकिस्तान के वार्षिक उत्सव में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उच्चायोग ने कहा कि बैसाखी समारोह की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने 12-21 अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान में होने वाले वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारत के सिख तीर्थयात्रियों को 2,856 से अधिक वीजा जारी किए हैं। पाक उच्चायोग के प्रभारी डी अफेयर्स आफताब हसन खान ने ने यात्रियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा तीर्थयात्रियों को हार्दिक बधाई और उन्हें एक पुरस्कृत और पूर्ण यात्रा की कामना करते हैं। पाकिस्तान पवित्र धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने और प्रदान करने में बहुत गर्व महसूस करता है।

15 करोड़ रु. के लिए 15 किलो घी का कोड वर्ड, सुकेश ने केजरीवाल पर लगाया आरोप

नई दिल्ली। सुकेश ने दावा किया है कि चैट में 15 करोड़ रुपये को 15 किलो घी कहकर संबोधित किया गसुकेश ने दावा किया है कि चैट में 15 करोड़ रुपये को 15 किलो घी कहकर संबोधित किया गया है, किसी को पता ना चले इसलिए कोड वर्ड में बात की गई ाया है, किसी को पता ना चले इसलिए कोड वर्ड में बात की गई। भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने केजरीवाल पर दक्षिण समूह और बीआरएस पार्टी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। सुकेश ने दावा किया कि उनके और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल के बीच चैट के स्क्रीनशॉट हैं और ये उक्त चैट टीआरएस कार्यालय को 15 करोड़ रुपये की डिलीवरी के संबंध में केजरीवाल के निर्देशों को दिखाते हैं। सुकेश ने दावा किया कि चैट स्पष्ट रूप से आपके (केजरीवाल) सांठगांठ को साउथ ौप और टीआरएस के नेता के साथ पुष्टि करेगा, जो शराब घोटाले में जांच के दायरे में है।

विकलांग बच्चों के स्कूलों से जुड़ा मामला अब बनेगा केजरीवाल के लिए परेशानी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक नया विवाद सामने आ रहा है। इस

बार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार पर अपनी विफलता छुपाने के लिए बार-बार हाई कोर्ट में झूठे बयान देने को लेकर तीखी आलोचना की है। दिल्ली एलजी कार्यालय के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा है कि शिक्षा विभाग और इससे पहले विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में केजरीवाल सरकार द्वारा बार-बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने पर एलजी ने गंभीरता से विचार किया है। एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करें ताकि हाईकोर्ट को गुमराह किया जा सके और अदालत को मामले की तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया जा सके।

देवभूमि में लैंड जिहाद को पनपने नहीं देंगे, अवैध मजारों को करेंगे ध्वस्त- धामी

देहरादून। उत्तराखंड में अवैध मजारों को लेकर राजनीतिक चर्चा लगातार जारी है। इन सबके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देवभूमि में लैंड जिहाद को पनपने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करेंगे। धामी ने आगे कहा कि यह नया उत्तरखंड है, यहां अतिक्रमण करना तो दूर की बात, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राज्य में वन भूमि पर 1000 से अधिक अनधिकृत मजारें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कालाढूंगी में राजकीय इंटर कॉलेज में 95 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के बाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एक हजार से अधिक स्थानों पर मजारें बन चुकी हैं। खुदाई करने पर उसके नीचे कोई अवशेष नहीं मिला।

बिहार विधान परिषद में भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी, 75 सदस्यीय सदन में अब 24 सीटें

पटना। बिहार विधान परिषद में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हाल में ही 5 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 75 सदस्य इस सदन में भाजपा के पास 24 सीटें हो गई है। वहीं, जदयू को नुकसान हुआ है। जदयू की सीट 24 से घटकर 23 हो गई है। 5 सीटों में से भाजपा ने कहा अपनी एक सीट बचाई तो वहीं एक और सीट पर जीत हासिल की। भाजपा ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में 2 सीटें जीती। वहीं, 2 सीटों पर महागठबंधन विजयी रहा। महागठबंधन ने कोसी और सारण स्नातक क्षेत्र में जीत हासिल की। वहीं, सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ट्वीट किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा. श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा बिहार विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी हैं, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को हार्दिक बधाई। बिहार बिजेपी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जदयू को पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

एंटनी का भाजपा में शामिल होना छोटी घटना नहीं

अजय सेठिया

देश के पूर्व रक्षा मंत्री, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने को सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि इतने बड़े कांग्रेसी नेता का बेटा भाजपा में शामिल हुआ है। ए.के. एंटनी आत्मग्लानि के शिकार हैं, क्योंकि उनके बेटे ने भाजपा में शामिल होते समय सभी कांग्रेसियों को गांधी परिवार का गुलाम बता दिया, जिनमें वह खुद भी शामिल हैं7 ए.के. एंटनी ने अपनी झेंप मिटाने और वफादारी दिखाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जाकर मीडिया के सामने सफाई दी। इस सफाई में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा देश के लिए काम करना सिखाया है, न कि एक परिवार के लिए। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना, वह एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गया है जो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। वह इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते, उनके लिए यह गलत और पीड़ादायक है। ए.के. एंटनी को यह घटना दिल पर नहीं लेनी चाहिए, उन्हें गांधी परिवार के सामने जाकर सफाई देने की जरूरत नहीं थी। उन्हें याद करना चाहिए कि उन्होंने खुद 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद गांधी परिवार को क्या रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा था कि कांग्रेस को मुस्लिमपरस्ती बंद करनी चाहिए। कांग्रेस के उन नेताओं पर नकेल डालनी चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस की छवि हिन्दू विरोधी पार्टी की बना दी है। अल्पसंख्यकों को खुश करने की कांग्रेस की नीति का उलटा असर पड़ा, हिन्दू कांग्रेस से बेहद नाराज हो गए, जिसका भाजपा को फायदा मिला। हालांकि यह रिपोर्ट अब कांग्रेस मुख्यालय के किसी कोने में धूल फांक रही होगी। लेकिन एंटनी ने अपने बेटे के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा को साम्प्रदायिक पार्टी कह कर अपनी रिपोर्ट की याद

दिला दी, जिसमें उन्होंने खुद लिखा था कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण करके अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पंहुचाया है। जब वह भाजपा को साम्प्रदायिक पार्टी कह रहे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने खुद कांग्रेस को साम्प्रदायिक कहा था। लेकिन अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने को इस नजरिए से देखा ही नहीं जाना चाहिए कि 50 साल से कांग्रेस परिवार का हिस्सा रहे एक परिवार का सदस्य भाजपा में शामिल हुआ है। इस घटना को इसकी पृष्ठभूमि से समझना चाहिए, और पृष्ठभूमि यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्यारा और दंगाई बताते हुए जब बीबीसी ने उनके खिलाफ एक डाक्यूमेंट्री जारी की थी, तब उन्होंने बीबीसी के खिलाफ स्टैंड लिया था, जिस पर कांग्रेस खफा हो गई थी। उनका स्टैंड यह था कि कांग्रेस का भारतीय न्यायपालिका के फैसलों को दरकिनार करके बीबीसी जैसे विदेशी संस्थान को महत्व देना देश हित में नहीं है। जबकि कांग्रेस भारतीय अदालतों के फैसलों को दरकिनार करके बीबीसी की डाक्यूमेंट्री को मुद्दा बना रही थी, क्योंकि इस डाक्यूमेंट्री में दंगों के लिए मोदी को कसूरवार ठहराया गया था, जो 2002 से कांग्रेस का स्टैंड रहा था। ए.के. एंटनी ने कहा है कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा देश के लिए काम करना सिखाया है, न कि एक परिवार के लिए, तो उनके बेटे अनिल ने जनवरी में बीबीसी के खिलाफ स्टैंड लेकर अपने पिता की शिक्षा के अनुसार ही काम किया था। क्योंकि उस समय अनिल ने कहा था कि बीबीसी का समर्थन करने से हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता कमजोर होगी। अनिल एंटनी का भाजपा में शामिल होना कोई मामूली घटना नहीं है, इसे न तो सिर्फ एक परिवार के नजरिए से देखना चाहिए, न ही राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्प्रभुता के नजरिए से देखना चाहिए। अलबत्ता राजनीतिक नजरिए से भी देखना चाहिए। दो साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए टॉम वडक्कन के साथ जोड़कर देखना चाहिए, यह भाजपा की ईसाईयों को अपने साथ लाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। गोवा और पूर्वोतर में ईसाईयों का दिल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के ईसाईयों को जोड़ने का फैसला किया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने खुद कोच्ची में केरल भाजपा की कोर कमेटी की बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने केरल यूनिट द्वारा अपने जनाधार को न बढ़ा पाने पर नाराज़गी का इज़हार किया था। वह इस बात से खफा थे कि 2016 में जहां भाजपा विधानसभा की एक सीट जीत गई थी, वहीं 2021 में एक भी सीट नहीं जीत पाई। मोदी ने इस बैठक में ईसाई समुदाय पर ध्यान केन्द्रित करने का मन्त्र दिया था। ऐसा पहली बार नहीं था कि मोदी ने ईसाई समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया था, इससे पहले जुलाई 2022 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने पार्टी नेताओं को ग़ैर-हिंदुओं से संपर्क बढ़ाने की सलाह दी थी। इस बैठक में उन्होंने उत्तरपूर्वी प्रांतों के भाजपा नेताओं से कहा था कि वे केरल का दौरा करें, और ईसाई समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए पार्टी की ओर से किए जा रहे प्रयासों को उजागर करें। कोच्चि बैठक में मोदी की झिड़की के एक हफ्ते के बाद, भाजपा ने मिशन ईसाई के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल में पार्टी के मामलों का प्रभारी नियुक्त कर दिया। पिछले महीने सायरो मालाबार कैथलिक चर्च के आर्कबिशप जोसफ के उस बयान ने खलबली मचा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा किसानों की समस्याओं पर विचार करे तो केरल के ईसाई भाजपा का समर्थन कर सकते हैं।

एक शर्त, एक आदेश पर बंद हो जाएंगे मदिरालय : मुख्यमंत्री

■ राजस्व से अधिक राज्य की जनता प्यारी

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में सपाट तौर पर कह दिया कि एक आदेश पर पूरे सूबे की मदिरालय बंद हो जाएंगे, शर्त यह है कि छत्तीसगढ़ के नागरिक इसका सेवन करना छोड़ दें। राजस्व से अधिक मुझे सूबे की जनता अधिक प्यारी है। उन्होंने कहा कि यहां पर उपस्थित लोग यह शपथ लें कि वे मदिरा का सेवन आज से नहीं करेंगे और इसे हमेशा के लिए त्याग देंगे। यही बात गुडाखू करने वालों पर भी लागू होती है। मैं एक आदेश पर शराबबंदी कर देता हूं।

दुर्ग में भेंट मुलाकात के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश में शराबबंदी किए जाने की मांग की। महिला ने कहा, शराब सेवन से कई परिवार परेशानी में हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब ही नहीं समर्पण नशा बंदी की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने एक आदेश पर प्रदेश में शराबबंदी हो जाएगी, लेकिन लाकडाउन के दौरान हमने देखा है जब पूरा देश बंद था तो भी अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, क्योंकि लोग इसका

सेवन कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि लाकडाउन में शराब नहीं मिलने पर रायपुर में सैनिटाइजर का सेवन से तीन लोगों की मौत हो गई थी। बिलासपुर में भी एक दवा का सेवन से लोगों को मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि जनता के जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, लेकिन लोग भरोसा दिलाएं कि शराब सेवन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब ही नहीं संपूर्ण नशाबंदी की बात होनी चाहिए। लाकडाउन में शराब ही नहीं लोगों ने गुड़ाखू भी ऊंची कीमत पर खरीद कर उसका सेवन किया। नशाबंदी के लिए सामाजिक जागरूकता की जरूरत है।

भेंट-मुलाकात के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि कका गैस सिलिंडर की कीमत कम करवा दो, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी कीमत केंद्र में बैठी सरकार तय करती है, राज्य सरकार नहीं। उन्होंने कहा कि पहले गैस सिलिंडर के दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी और सरोज पांडेय धरना पर बैठ जाते थे। मुख्यमंत्री ने उक्त महिला से कहा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल आएंगे तो उनसे कहना कि गैस सिलिंडर के दाम कम करवा दें।

मुख्यमंत्री ने किया स्वामी आत्मानंद स्कूल के नये भवन का लोकार्पण

दुर्ग। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के महेनजर नये स्कूल भवन में स्मार्ट क्लास रुम, एक्टिविटी रुम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब बनाए गए हैं। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्कूल के बच्चों से बातचीत की और एक्टिविटी रुम, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास रुम का अवलोकन किया। यहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए एक करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है नया स्मार्ट क्लास रुम, एक्टिविटी रुम, लाइब्रेरी तथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से सुसज्जित लैब। स्कूल के पुराने भवन को भी किया गया है रिनोवेट।

किसानों को डेढ़ से दोगुना मूल्य में बेच रहे थे स्टांप, दो दुकान सील

बेमेतरा। बेमेतरा जिले में तहसील कार्यालय के पास किसानों के स्टांप विक्रेताओं की मनमानी के संबंध में लगातार शिकायत मिलने पर एसडीएम सुरुचि सिंह ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई की। स्टांप विक्रेता छोटे स्टांप जैसे 10 रुपए और 20 रुपए के स्टाम्प को स्टॉक में नहीं होना बताकर ज्यादा रुपए में बेचते पाया गया। उनकी ओर से 100 एवं 50 के स्टांप को डेढ़ से दोगुना मूल्यों पर बेचते पाया गया।

एसडीएम सुरुचि सिंह की जांच के दौरान शिकायतों को सही पाया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि स्टांप विक्रेताओं ने अपना लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया है। बाद में विक्रय किए गए स्टांप को 13 मार्च 2023 के तारीख पर प्रविष्ट कर विक्रय कर रहे थे। ऐसे में बिना लाइसेंस के दुकानों को सील कर दिया गया है। महावीर स्टांप विक्रेता, खंडे स्टांप विक्रेता की दुकान को सील किया गया। उन्होंने शेष विक्रेताओं को यह समझाइश दी है कि वह नियमानुसार स्टांप के विक्रय का चस्पा करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता न करें। उक्त कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक, पटवारी सहित राजस्व टीम शामिल रहे।

भवन निर्माण में लगे श्रमिक की बिजली करंट से मौत का मामला

मृत आदिवासी युवक के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा दे : महेन्द्र नेताम

नगरी। ग्राम बोकराबेड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य करते समय बिजली करंट की चपेट में आने से मृतक आत्माराम के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा राशि देने की मांग भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष महेंद्र नेताम ने की है। युवक आत्माराम अपने मां-बाप का एकलौता कमाऊ पुत्र था, उनकी डेढ़ साल की छोटी बच्ची है। अब पत्नी का भी सहारा छिन गया, साथ ही एक विवाह योग्य छोटी बहन भी है। इन सभी की परवरिश की जिम्मेदारी आत्माराम पर थी। उक्त कार्य में नियमों को ताक पर रखकर कार्य में लगे ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है।

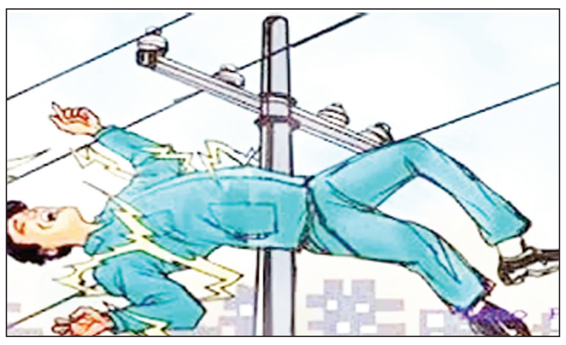

स्थल निरीक्षण करने के बाद पाया गया कार्य में घोर लापरवाही बरती गई है इसमें तकनीक की भी घोर लापरवाही दिख रही है। नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सूचना फ्लक्स का निर्माण नहीं किया गया है। निर्माण स्थल से लगा हुआ बिजली का मेन लाइन गुजरी है जो नियमों का खुला उल्लंघन है। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बिजली बंद करने की सूचना नहीं दी गई थी। साथ ही बिजली तार से भवन की दूरी का भी ध्यान नहीं दिया गया। इसमें प्रशासन की लापरवाही भी दिख रही है प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है एक जवान बेटा मौत के मुंह में समा गया। साथ ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एवं प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में सीमेंटेड ईंट के बजाय लाल ईंट से भवन निर्माण किया जा रहा है जो कि शासन के नियमों का अनदेखी एवं सीधा सीधा उल्लंघन है।

छत्तीसगढ़ के मुखिया अन्य प्रदेश में जाकर श्रेय लेने के लिए वहां के निवासियों के लिए पचास लाख की घोषणा करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में खासकर पांचवी अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी परिवार की मुखिया के मृत्यु पर न तो आज तक संबंधित क्षेत्र के विधायक पहुंची है और ना ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यह प्रशासनिक घोर लापरवाही का परिणाम है। आदिवासियों को भगवान भरोसे छोड़कर मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है।

जिलाध्यक्ष महेन्द्र नेताम ने कहा है कि मृतक आत्माराम के परिजनों को यदि एक करोड़ मुआवजा राशि नहीं दी गई और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध एफ आई आर कर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो अजजा मोर्चा आदिवासी समाज के साथ वाजिब हक के लिए सत्याग्रह के लिए बाध्य होगी।

अपने ही वादों में उलझते जा रहे सीएम मानदेय से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता

भाजपा नेता दुर्गानंद का तंज

बालोद। हाल ही में प्रदेश सरकार ने बेरोजगार लोगों को 25 सौ रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत की है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गानंद साहू ने सीएम बघेल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अपनी ही बातों में प्रदेश के मुख्यमंत्री फंसते जा रहे हैं। एक तरफ तो बेरोजगारों को 2500 प्रतिमाह भत्ता दे रहे हैं तो दूसरी ओर स्कूल के सफाई कर्मियों का मानदेय उससे कम है। इसके कारण कहीं ना कहीं असंतोष की भावना प्रदेश के कर्मचारियों में है। वहीं, खबरें यह भी है कि कर्मचारी सामूहिक इस्तीफे कि पेशकश कर सकते हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को को लोगों के जज्बातों के साथ खेलना बड़े बेहतर ढंग से आता है। वे यह सीख गए हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे रिझाया जाए, परंतु छत्तीसगढ़ के लोग कर्मठ लोग हैं। वह मुफ्त के 2500 देने से अच्छा रोजगार और अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी स्कूल, सफाई कर्मचारी, रसोईया जो कि दिन भर मेहनत कर बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं उनका मानदेय बेरोजगारों से भी कम है।

क्या सरकार के पास नहीं कर्मचारियों का डेटा

दुर्गानंद साहू ने कहा कि सरकार के सामने जब भी नियमितीकरण की बात आती है, तो वे कर्मचारियों के डाटा मंगाने का बात कहती है। क्या चार वर्षों में अभी तक डाटा प्रबंधन नहीं हो पाया है या फिर सरकार को यह नहीं पता कि आखिर वह कितने कर्मचारियों को सरकारी खजाने से पैसा दे रही है। जाहिर सी बात है एक परिवार के मुखिया को इतना तो पता रहता है कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं या फिर छत्तीसगढ़ के मुखिया को उनके परिवार की चिंता ही नहीं है। आखिर जिला प्रशासन या अन्य विभागों से तो अनियमित कर्मचारियों की तनख्वाह जारी होते होंगे इतना समय क्यों लग रहा है अनियमित कर्मचारियों के डाटा एकत्र करने में यह महज एक छलावा और दिखावा है और यह कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं।

जिला चिकित्सालय बेमेतरा के विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा में हुआ सुधार

बेमेतरा। कलेक्टर बेमेतरा पदुम सिंह एल्मा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी एल टंडन के निर्देशानुसार सिविल सर्जन डॉ संत राम चुरेंद्र के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय बेमेतरा के स्वास्थ्य सुविधा में सकारात्मक पहल करते हुए विभिन्न सुविधाएं नियमित उपलब्ध किये गए हैं।

जिला चिकित्सालय बेमेतरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सत्य प्रकाश कोसरिया ने जुलाई 2022 में ड्यूटी ज्वाइन की उन्होंने एनेस्थेटिक की अनुपस्थिति में आपातकालिन एवं प्लान सीजर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी फिर भी सिविल सर्जन के प्रयास द्वारा आसपास के जिलों से एनेस्थेटिक की व्यवस्था कर तत्काल इमरजेंसी के 30 सीजर किए गए एवं एनेस्थेटिक डॉ अमिताभ साहू के ज्वाइन करने के बाद सिजेरियन सेक्शन की सेवाएं अब प्रत्येक दिन (इमरजेंसी एवं इलेक्टिव) किया जा सकेगा जिसमें सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतना विशेषज्ञ व ऑपरेशन थिएटर के अन्य टीम के सदस्यों की मदद से जरूरतमंदों को यहां सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिला चिकित्सालय में अब तक 50 सिजेरियन सेक्शन हो चुकी है वही हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ अंकुर कुंडु के पदस्थापना होने पर हड्डी रोग संबंधित सेवाएं भी अब नियमित रहेगी।

जिला चिकित्सालय बेमेतरा में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ समता रंगारी के उपस्थिति से प्रत्येक बुधवार को दिव्यांग व्यक्तियों का प्रमाण पत्र बनवाने की समस्या दूर हो रही है, प्रत्येक शनिवार को मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. सुचिता गोयल के लगातार उपस्थिति से जिले के मनोरोगियों को और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ दीपक मीरे से एस एन सी यू वार्ड, एन आर सी, बच्चों के इलाज में बहुत लाभ मिल रहा है। जिला चिकित्सालय में दंत रोग डॉ विजया रमन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉ, मेडिसिन रोग विशेषज्ञ डॉ खगदेव साहू नियमित सेवाएं दे रहे हैं इसके साथ विभिन्न चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं जिनसे जिला चिकित्सालय बेमेतरा में स्वास्थ्य सुविधा में सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो गया है। नाक कान गला विशेषज्ञ के आने से अब संबंधित मरीजों को अन्य जिला नहीं जाना पड़ता। इनकी सेवाएं नियमित रूप से जिला चिकित्सालय में आए मरीजों को मिल रहा है। इसके अलावा एचआईवी काउंसलिंग एवं टेस्टिंग, लिंक ए आर टी, यौन रोग सुरक्षा क्लिनिक, जिला क्षय केंद्र में टी बी जांच सुविधा, एक्स रे, सोनोग्राफी, फिजियो थेरेपी, विभिन्न लैब टेस्ट, ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट, ट्रांसफ्यूजन, ई सी जी आदि की सुविधा निःशुल्क नियमित रूप से है असुविधा होने पर एम सी एच, जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क व्यवस्था है जिसमे मितानिन मरीजों की आवश्यकता अनुसार नियमित सहयोग कर रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सिरसिदा में मनाया गया भाजपा स्थापना दिवस

नगरी। ग्राम सिरसिदा बूथ क्रमांक 183 में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस के मनाया गया। इस अवसर पर पं दीनदयाल उपाध्याय जी पं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई जी का स्मरण किया गया जिसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुना गया तथा मिष्ठान वितरण किया गया एवं वरिष्ठ नागरिकों का शाल एवं श्रीफल भेंट करके सम्मान किया गया सम्मान किया गया एवं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के निवास पर ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी जी बूथ अध्यक्ष रूपेश साहू पूर्व सरपंच सौहद्रा नेताम पूर्व बूथ अध्यक्ष चंद्रभान साहू नगरी सोशल मीडिया संयोजक चित्रांश नागवंशी सौहद्री बाई मिश्रा चंद्रपाल मिश्रा चित्रेखा साहू गायत्री साहू लोकेश एल्मा लक्ष्मी निर्मलकर मोहनी बाई एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विधायक ने हनुमान जयंती पर की खुशहाली मांगी

भिलाई। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सुबह सेक्टर 9 हनुमान मंदिर पहुंचे। जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी की पूजा आरती की। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया और श्रीफल श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए विधायक श्री यादव ने पूरे भिलाई वासियों के हित और विकास,सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हनुमानजी की जयंती के अवसर पर मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ लगी थी। लेकिन वे वहाँ वीआईपी बन कर नहीं गए बल्कि एक आम एकदम सामान्य भक्त की तरह लाइन में लगकर मंदिर पहुंचे फिर पूजा अर्चना की। अपनी भक्ति के साथ वे भी धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस दौरान वे तू रक्षक काहू को डरना लिखा हनुमान जी की फोटो वाली टी शर्ट पहने हुए थे पूजा समाप्ति के बाद विधायक श्री यादव सेक्टर 9 मंदिर परिसर स्थित जय हनुमान सेवा वाहिनी द्वारा आयोजित भंडार कार्यक्रम में शामिल हुए। जहाँ उन्होंने महाप्रसाद वितरण किए।

कुसमुंडा खदान में बेल्ट की चपेट में आने से मजदूर घायल

कोरबा। कोरबा के कुसमुंडा खदान में सुबह काम करने के दौरान एक ठेका कर्मी कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से उसमें बुरी तरह जा फंसा। जिसके बाद वहां मौजूद ठेका कर्मियों में हड़कंप मच गया व तत्काल इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद ठेका कर्मी को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है। कुसमुंडा खदान समानता कंपनी में सुबह पाली में काम करने गए ठेका कर्मी कन्वेयर बेल्ट की सफाई कर रहे थे इसी दौरान वह कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आकर बुरी तरह दब गए। इस घटना की जानकारी तत्काल वहां मौजूद अन्य ठेका कर्मियों ने अधिकारियों को दी, जिसके बाद कटर मशीन से कड़ी मशक्कत के बाद घायल ठेका कर्मी को बाहर निकाला गया, वही घायल मजदूर को तत्काल कोरबा अस्पताल पहुंचाया गया है।

दो आरोपियों को मिली 10-10 साल की कारावास की सजा

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में दो आरोपी को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पंकज कुमार सिन्हा ने बीते दिनों सुनाया। उन्होंने ग्राम झाल, थाना नवागढ़ निवासी आरोपी किशोर मिरे, प्रभात मिरे को धारा 307, 34 के तहत फैसला दिया है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि यह मामला 28 जुलाई 2022 की है। प्रार्थी शिवकुमार पाटले ने 28 जुलाई को थाना थाना नवागढ़ में शिकायत दर्ज कराया कि 28 जुलाई को उसका लड़का टीकाराम अपनी पत्नी हेमलता पाटले और दो बच्चों को लेकर मोटर साइकिल से रायपुर जाने के लिए घर से निकले थे। करीब साढ़े 11 बजे आरोपी प्रभात मिरे और किशोर मिरे दोनों मिलकर टीकाराम के सिर में लोहे के धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण वह जमीन में गिर गया।

110 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

रायगढ़। सारंगढ़ जिले के डोंगरीपाली पुलिस ने दो गांजा तस्करों को बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी जब्त किया है। पुलिस ओडिशा बॉर्डर पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान थाना डोंगरीपाली पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि दो शख्स एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पकड़े गए तस्करों की पहचान अजय कुमार सिंह और आनिध्य चंसोरिया के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त वाहन की जांच में 110 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है।

पीएचई के ईई व डीए को प्रमुख अभियंता ने लगाई फटकार

■ प्रमुख अभियंता और अतिरिक्त मिशन संचालक ने ली समीक्षा बैठक

जगदलपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जगदलपुर परिक्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रमुख अभियंता और अतिरिक्त मिशन संचालक जल जीवन मिशन रायपुर डॉ. एमएल अग्रवाल तीन दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। प्रमुख अभियंता डॉ. एमएल अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जगदलपुर परिक्षेत्र के जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक शहर के एक होटल में ली गई। इस बैठक में प्रमुख अभियंता ने जिला अधिकारियों से कार्य संपादन में आ रही दिक्कत तथा निराकरण के सम्बंध में चर्चा किए। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान कर जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और जल जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके इसके प्रयास करने की बात कही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में बस्तर संभाग के पीएचई के ठेकेदारों ने प्रमुख अभियंता केसमक्ष अपनी समस्या को रखते हुए बताया कि विभाग की कार्यशैली के चलते ठेकेदार टेंडर नहीं डालना चाहते हैं। ठेकेदारों की मुख्य शिकायत टाइम एक्सटेंशन के लिए 6 प्रतिशत राशि की कटौती किए जाने से ठेकेदार नाराज थे, जिस पर प्रमुख अभियंता डॉ. एमएल. अग्रवाल ने पीएचई के ईई और डीए को नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए फटकार लगाते हुए ठेकेदारों को प्रमुख अभियंता के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ठेकेदारों की कुछ परेशानी कम होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। पीएचई के ठेकेदारों ने कहना है कि टाइम एक्सटेंशन के लिए कटौती की गई 6 प्रतिशत राशि के वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

इस बैठक में सीई जगदलपुर जोन एकेसाहू, एसई सर्किल कोंडागांव जी बारापात्रे, प्रभारी सर्किल जगदलपुर जगदीश कुमार तथा बस्तर संभाग के सभी कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता,उप अभियंता, जिला सहयोगी तथा जिला समन्वयक उपस्थित थे। सर्व ठेकेदारों की समीक्षा बैठक हुई जिसमें प्रमुख अभियंता द्वारा उनके कार्य में आने वाले दिक्कतों को पुछा तथा समस्या का हर संभव समाधान निकालने का प्रयास किया।

अतिक्रमण दस्ते ने हटाया आम बाड़ी से अवैध कब्जा

■ आयुक्त के निर्देश पर आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु निगम बनाएगा बाउण्ड्रीवाल, होगी चौकीदार की तैनाती

कोरबा। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने पोड़ीबहार स्थित निगम की आम बाड़ी में कतिपय व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया तथा उनके द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जे.सी.बी. के माध्यम से हटाकर आम बाड़ी को अतिक्रमण से मुक्त कराया, वहीं आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण व चौकीदार कक्ष का निर्माण कर चौकीदार की तैनाती करने की कार्यवाही की जा रही है।

पोड़ीबहार क्षेत्र में लगभग 04-05 एकड़ जमीन पर निगम की आम बाड़ी स्थित है, तत्कालीन साडा कार्यकाल में निर्मित कराई गई उक्त आम बाड़ी में काफी संख्या में आम के फलदार वृक्ष स्थित हैं, कतिपय अवैध कब्जाधारियों द्वारा समय-समय पर उक्त आम बाड़ी में अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है, इसी कड़ी में 08-10 अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा कर आम बाड़ी में मकान आदि का निर्माण कर लिया गया था, अभी हाल ही में निगम अमले ने इन अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। आज

अतिक्रमण दस्ते ने प्रभारी अधिकारी श्री योगेश राठौर की अगुवाई में आम बाड़ी पहुंचकर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जे.सी.बी. के माध्यम से हटाकर आम बाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व ही आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने पोड़ीबहार क्षेत्र स्थित उक्त आम बाड़ी का भ्रमण कर आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किए जाने तथा आम बाड़ी को व्यवस्थित कर उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी के चारों बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, चौकीदार कक्ष का निर्माण व चौकीदार की तैनाती आदि के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद जाएंगे

हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को यहां सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद के दौरे के दौरान मोदी यहां परेड ग्राउंड में एक जनसभा में भी हिस्सा लेंगे। वह हैदराबाद के समीप एम्स बीबीनगर और पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे और रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति मंदिर शहर से जोड़ने वाली सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस तीन महीने से भी कम अवधि के भीतर तेलंगाना से शुरू की जाने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग साढ़े तीन घंटे कम हो जाएगा।

आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भाजपा में शामिल

नईदिल्ली। अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। यह पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लाइन का त्याग पत्र भेजकर कांग्रेस छोड़ने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के परिवार के कई सदस्य कांग्रेस में थे। कुछ समय पहले जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि वह पीएम मोदी से प्रभावित हैं। आज वह बड़ी छलांग लगाते हुए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेंगे क्योंकि एक विधायक और मंत्री के रूप में उनकी छवि बहुत साफ रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से राज्य दर राज्य पार्टी टूट रही, यह एक राज्य की बात नहीं।

सिंधिया और आजाद पर अशोक गहलोत का पलटवार

जयपुर। हाल में ही भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर कुछ सवाल उठाए थे। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी को निशाना बनाया था। अब इसी के बाद कांग्रेस की ओर से दोनों नेताओं पर तीखा प्रहार किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि सोचा नहीं था कि ये दोनों राहुल गांधी के खिलाफ इतने नीचे स्तर की भाषा बोलने लगेंगे। गहलोत ने लिखा कि आजाद एवं सिंधिया, राहुल के खिलाफ ऐसी निम्नस्तरीय भाषा बोलने लगेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता थक चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। गहलोत ने आगे कहा कि इसलिए कांग्रेस से गए इन नेताओं को टास्क दिया गया है। ये सब जिंदगीभर जिस विचारधारा से लड़ने की कसमें खाते थे आज भाजपा नेताओं के इशारे पर उसी फासीवादी विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं।

मोदी शासन में अमीर और अमीर होता जा रहा है : सिब्बल

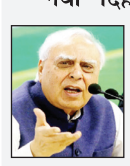

नयी दिल्ली। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने सामाजिक न्याय के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सरकार के शासन ''अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है।'' भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा को विकास, विश्वास और नए विचार का पर्याय बताते हुए कहा था कि सामाजिक न्याय उनकी पार्टी की विचारधारा का आधार है। सिब्बल ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जीती है और अक्षरश: इसका पालन करती है। जबकि तथ्य है- 2012-2021 तक अर्जित धन का 40% केवल 1% आबादी के पास गया। 2022 में अडाणी की संपत्ति में 46% की वृद्धि हुई। 64% जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) निचले तबके से 50% आया, जबकि केवल 4% शीर्ष 10% ने अदा किया।' सिब्बल ने कहा, 'अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है।'

आरक्षण मुद्दे पर डीके शिवकुमार का भाजपा पर पलटवार

कर्नाटक। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य में आरक्षण के मुद्दे को खत्म करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही आरक्षण के मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने बिना किसी परेशानी के दो सूचियां बना ली हैं, जबकि भाजपा अभी तक एक सूची भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा का समर्थन कर रहे किच्छा सुदीप पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुत सारे फिल्मी सितारे आते जाते रहते हैं। फिल्म और राजनीति दो अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुदीप के समर्थन से चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस-जेडीयू दोनों ही एलान कर चुके हैं कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनती है तो वह इस आरक्षण को फिर से लागू करेंगे। वहीं, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस मुस्लिम वोटों के चक्कर में ऐसा वादा कर रही हैं।

2024 में फिर होगी भाजपा की जीत, केंद्रीय गृहमंत्री का राहुल गांधी पर वार

लोकतंत्र नहीं, गांधी परिवार खतरे में है : शाह

लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश दौरे थे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में उन्होंने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सिराथू में आयोजित कौशांबी महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में अरबों की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ उत्तर

प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि 2024 में एक बार फिर से भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया। अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को ही संसद समाप्त हुई। आज़ादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा करे बिना संसद समाप्त हुई हो। विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया।

शाह ने साफ तौर पर कहा कि इसका कारण कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया... राहुल गंधी इस सज़ा को चुनौती दें। आपने संसद के वक्त को बली चढ़ा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा इस बार फिर से 300 के पार सीटें लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों या कोई भी हों मोदी को गाली गलोज के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है। उन्होंने कहा कि यह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि आपका परिवार खतरे में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारद और तुष्टिकरण के तीन नाखूनों में घेर कर रखा था।

पीएम के आदेश पर वित्तमंत्री अडानी को बचाने आगे आई हैं : अधीर रंजन

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम के आदेश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अडानी को बचाने और उन्हें क्लीन चिट देने के लिए आगे आई हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि इससे साबित होता है कि कुछ तो छिपा हुआ है जो सरकार सामने नहीं आना चाहती...राहुल गांधी इस सत्ताधारी सरकार के भ्रष्टाचार, दुराचार और कुशासन के खिलाफ बोलने के लिए कृतसंकल्प हैं। सीतारमण ने अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे आरोप लगाने की आदत हो गई है।

सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर राहुल गांधी वास्तव में सोचते हैं कि अडानी को ये सब चीजें (अनुचित लाभ) दी गई हैं, तो यह सच नहीं है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत हो गई है। हम 2019 के चुनावों से पहले इसे देख चुके हैं, अब वह फिर से ऐसा कर रहे हैं। वह इन सब झूठे आरोपों से कोई सबक नहीं सीखते हैं।

सीतारमण ने यह भी सवाल किया कि गांधी ने केरल सरकार द्वारा अडानी को दिए गए अनुचित लाभ और राजस्थान में कंपनी की एक सौर ऊर्जा परियोजना के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। वित्त मंत्री ने कहा, यह (तत्कालीन) कांग्रेस सरकार (केरल में) थी, जिसने अडानी को विझिंजम बंदरगाह दिया था। यह किसी निविदा के आधार पर नहीं दिया गया था। अब वह (कांग्रेस) सरकार नहीं है, बल्कि माकपा नीत सरकार है। लेकिन उन्हें यह पूछने और मांग करने से किसने रोका कि केरल उस आदेश को रद्द कर दे?

कर्नाटक के प्रत्याशियों का फैसला 9 को कर सकती है भाजपा

नईदिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल आपने अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने कर्नाटक में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। हालांकि, सत्तारूढ़ भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। इसको लेकर भी कांग्रेस की ओर से राजनीति हो रही है। कांग्रेस लगातार भाजपा से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का तो दावा है कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है। हालांकि, इस को लेकर भाजपा की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने ज्यादातर सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी एक भी सीट का ऐलान नहीं कर पाई। सुरजेवाला को भाजपा नेता और सरकार में मंत्री के सुधाकर ने जवाब दिया है। के सुधाकर ने कहा कि मैं सुरजेवाला से पूछना चाहता हूं कि वे हमारी लिस्ट को लेकर इतने परेशान क्यों हैं, क्या उन्हें अपने सदस्यों पर भरोसा नहीं है, वे क्यों हमारी लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? यह हमारी रणनीति का हिस्सा है, हमें पता है कब घोषणा करनी है। इन सब के बीच खबर यह है कि यह है कि भाजपा इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कर्नाटक चुनाव को लेकर 9 अप्रैल को होगी। इसमें प्रत्याशियों के नामों पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक के बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि, माना जा रहा है कि भाजपा ने हर एक सीट पर दो से तीन नामों का चयन कर लिया है। इनमें से एक नाम की पुष्टि होनी बाकी है।

लोकतंत्र को कुचल रहे तमिलनाडु के राज्यपाल : चिदंबरम

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर उनकी उस टिप्पणी के लिए निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोकना उनके विवेक पर निर्भर करता है। साथ ही, चिदंबरम ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा की ओर से नियुक्त राज्यपाल अपनी शक्तियों का उल्लंघन कर लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने को 'विचित्र और अजीबोगरीब परिभाषा दी है और कहा है कि इसका मतलब है कि विधेयक खत्म हो चुका है। राज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहा कि सही मायने में जब कोई राज्यपाल बिना किसी वैध कारण के सहमति नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र मर चुका है। राज्यपाल विधेयक को मंजूरी देने या रोकने या वापस करने के लिए बाध्य है। अगर विधेयक फिर से पारित हो जाता है, तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य है। चिदंबरम ने कहा कि राज्यपाल केवल एक संवैधानिक पदाधिकारी है और प्रतीकात्मक प्रमुख है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की शक्तियां मुख्यत- प्रतिबंधित हैं और अधिकांश मामलों में उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। अपनी शक्तियों का उल्लंघन कर भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। राज्यपाल रवि की टिप्पणी की तमिलनाडु में द्रमुक नीत सरकार ने भी आलोचना की है और कहा है कि मंजूरी में अनावश्यक देरी करना राज्यपाल की ओर से कर्तव्य में लापरवाही है।

राहुल की यात्रा से जबरदस्त नैरेटिव बना : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त नैरेटिव बना है, जो वास्तव में परिवर्तनकारी था। कांग्रेस नेता ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि राहुल की इस यात्रा से भाजपा हताश है और अब ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया। लिखा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने एक जबरदस्त राष्ट्रीय नैरेटिव बनाया, जो वास्तव में परिवर्तनकारी था। हताश भाजपा उस नैरेटिव को तोड़ने और उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अफसोस की बात है कि इसमें कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए महानुभाव भी शामिल हैं, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। एक अन्य ट्वीट के जरिए जयराम रमेश ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने खाद्य वस्तुओं के दाम का एक चार्ट पोस्ट करते हुए लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बढ़ती आर्थिक असमानता थी, जिसका मुख्य कारण आसमान छूती महंगाई है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल से कैसे घरेलू बजट प्रभावित हुआ है। इसके पहले गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। कहा, पीएम मोदी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बात नहीं करते हैं। वह अदाणी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की विपक्ष की मांग से ध्यान हटाने के लिए संसद में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

खेल

प्रमुख समाचार

बांग्लादेश ने आयरलैंड को हराकर सीरीज पर किया कब्जा

मीरपुर। आखिरकार बांग्लादेश ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। बांग्लादेश ने वनडे सीरीज 2-0 से और टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम किया था। एकमात्र टेस्ट में 7 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। रहीम ने पहली पारी में 126 रन बनाए थे। दूसरी पारी में नाबाद 51 रन का योगदान दिया। एक टेस्ट की दो पारी में 177 रन बनाए। 145 टेस्ट के बाद आईसीसी एलीट पैनल अंपायर के रूप में अलीम डार ने अंतिम पारी खेली। दोनों टीमों ने डार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अनुभवी मुश्फिकर रहीम की शानदार बल्लेबाजी से बांग्लादेश ने शुक्रवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में चौथे दिन लंच के कुछ देर बाद ही सात विकेट से जीत हासिल की। आयरलैंड ने पहली पारी में 214 रन बनाए जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 369 रन बनाकर मजबूत बढ़त हासिल की। आयरलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 292 रन बनाए और इस तरह से बांग्लादेश के सामने 138 रन का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश ने तीन विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल किया। पहली पारी में 126 रन बनाने वाले रहीम ने दूसरी पारी में नाबाद 51 रन बनाए। उनके अलावा मोमिनुल हक ने नाबाद 20 रन बनाए। लिटन दास ने 23 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। तमीम इकबाल ने 31 रन का योगदान दिया। इससे पहले आयरलैंड ने अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 286 रन से आगे बढ़ाई और बांग्लादेश ने 36 मिनट के अंदर उसके बाकी बचे चार विकेट हासिल कर दिए। तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ने एंडी मैकब्राइन को बोल्ड किया जो अपने कल के स्कोर में केवल एक रन जोड़ पाए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

10 फीसदी तक सस्ती मिलेगी सीएनजी-पीएनजी

नईदिल्ली। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को शनिवार से राहत मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को घरेलू गैस की कीमतें तय करने को लेकर बनाई गई किरीट पारिख कमिटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब देश में गैस के दाम नए फॉर्मूले के आधार पर तय किए जाएंगे। इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही हैं कि शनिवार 8 अप्रैल से सीएनजी और पीएनजी के दामों में कटौती देखने को मिल सकती हैं। नए फॉर्मूले के तहत अब प्राकृतिक गैस की कीमत इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट के औसत मासिक दाम का 10 फीसदी होगी। नए फॉर्मूले के आधार पर कीमतों का निर्धारण करने पर उम्मीद जताई जा रही है कि पीएनजी की कीमत में लगभग 10 फीसदी और सीएनजी की कीमत में 5 से 6 रुपए प्रति किलो की कमी आएगी।

ओपेक+ देशों का कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला

नई दिल्ली। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओआईसी) की ओर से विकसित अर्थव्यवस्थाओं से कम मांग की आशंका में कच्चे तेल के उत्पादन में 16 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने के फैसले से मध्यम से दीर्घ अवधि में भारत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत अपनी 4.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन की जरूरतों का 85 प्रतिशत क्रूड ऑयल आयात करता है। क्रूड ऑयल के हर बैरल की कीमत में अगर 10 डॉलर का इजाफा होता है तो भारत का आयात बिल सालाना 15 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। जानकारों के अनुसार यह देश की जीडीपी का करीब 0.51% है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि सउदी अरब और रूस समेत सभी ओपक प्लस देशों की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में कटौती का देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अवाडा एनर्जी को दामोदर वैली कॉरपोरेशन से मिली 421 मेगावॉट की सौर परियोजना

नईदिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अवाडा एनर्जी ने शुक्रवार को बताया कि उसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 421 मेगावाट की सौर परियोजना मिली है। परियोजना प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये दी गई। नीलामी में अवाडा को यह परियोजना 2.70 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिली है। अवाडा ने एक बयान में कहा, 'उसे डीव्हीसी की तरफ से आरईसी पॉवर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा आयोजित नीलामी में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी 421 मेगावॉट (डीसी) सौर पीवी परियोजना मिल गई है।' बोली शर्तों के अनुसार, यह समझौता दो इकाइयों के बीच 25 वर्षों के लिए हुआ है। यह परियोजना 18 महीने में शुरू हो जाएगी। इस संयंत्र से प्रतिवर्ष 75 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा पैदा होगी, जिससे 6,98,250 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होगा।

सेबी ने अनाधिकृत परामर्श सेवाएं देने को लेकर चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया

नईदिल्ली। पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने शुक्रवार को चार कंपनियों को स्वीकृति के बगैर निवेश परामर्श सेवाएं देने के लिए प्रतिभूति बाजारों से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कोर्स वर्क फोकस और इसके मालिक शशांक हिरवानी, कैपिटल रिसर्च के मालिक गोपाल गुप्ता और कैपर्स के मालिक राहुल पटेल को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार में भागीदारी करने से रोक दिया है। दो अलग-अलग आदेशों में, सेबी ने अपनी पड़ताल में पाया कि ये कंपनियां निवेश सलाहकार के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनाधिकृत निवेश सलाहकार सेवाओं में लगी हुई थीं।

छोटे उद्यमियों के ऋण की समस्या

अजीत रानाडे

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्यमियों को मजबूत करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में हालिया बदलाव की घोषणा की। छोटे उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी समस्या समुचित ब्याज दर पर समय पर कर्ज न मिल पाने की है। इसकी मुख्य वजह इस सेक्टर के लिए बैंकों से कम रकम की उपलब्धता है। बैंक इसे बहुत अधिक जोखिम का क्षेत्र मानते हैं। अर्थव्यवस्था में छोटे एवं मझोले उद्यमों के अत्यधिक महत्व को देखते हुए इसे मजबूत करने के हरसंभव प्रयास होने चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और निर्यात में ये उद्यम लगभग आधे हिस्से का योगदान करते हैं। देश में ऐसे उद्यमों की संख्या लगभग 6.40 करोड़ है। ये उद्यम सेवा क्षेत्र में भी योगदान करते हैं तथा इसमें मोची, पान दुकान या सैलून जैसी सेवाएं भी हैं, जहां एक व्यक्ति सेवा मुहैया कराता है। मैनुफैक्चरिंग में ही लगभग 12 लाख उद्यम हैं। इन आर्थिक इकाइयों को एक साथ सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम कहा जाता है।

अब निवेश या टर्नओवर के हिसाब से ऐसे उद्यमों को परिभाषित किया जाता है। एक करोड़ रुपये तक के निवेश या पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यम सूक्ष्म (माइक्रो), दस करोड़ रुपये तक के निवेश या पचास करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यम छोटे (स्मॉल) तथा पचास करोड़ तक के निवेश या 250 करोड़ के टर्नओवर वाले मध्यम (मीडियम) उद्यम माने जाते हैं। बीते वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत पहलें की हैं।

इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं समुचित ऋण, विपणन, तकनीक, वित्तीय साक्षरता

आदि का अभाव तथा कुछ ग्राहकों पर अति निर्भरता या सही प्रतिभा का उपलब्ध नहीं होना हैं। छोटे व मझोले उद्यमों का समर्थन समावेशी विकास की भावना के अनुरूप है क्योंकि वे करोड़ों परिवारों को रोजी-रोटी मुहैया कराते हैं तथा उनकी सफलता उनमें अर्थव्यवस्था में भागीदारी का भरोसा और सम्मान का भाव भरती है। इस क्षेत्र के सभी तरह के उद्यम देरी से भुगतान के रूप में एक बड़ी समस्या का सामना करते हैं। चूंकि उनके ग्राहक बड़े और रसूखदार होते हैं, तो वे ठीक से मोल-भाव भी नहीं कर पाते। अक्सर पिछले भुगतान को अगले ऑर्डर के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे में संभव है कि ग्राहक के पास हमेशा ही दस-बीस प्रतिशत बकाया रहता हो। मजबूरी की एक वजह यह भी है कि अधिकतर छोटे व मझोले उद्यमों के पास केवल एक बड़ा खरीदार होता है।

छह माह से अधिक देरी पर वे ग्राहक पर अदालती या दिवालिया संबंधी कार्रवाई भी नहीं कर पाते। अगर वे ऐसा करेंगे, तो उनका कारोबार ही बंद हो जायेगा। यह दोनों तरह की- निजी और सरकारी- बड़ी कंपनियों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, रेलवे के पास दस लाख छोटे वेंडर हैं, जिनका एक ही ग्राहक है। डन एंड ब्राडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार, छोटे व मझोले उद्यमों का लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बकाया है। इसका सालाना ब्याज ही एक लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अगर इस बकाये का भुगतान हो जाए, तो यह इस क्षेत्र को एक लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने जैसा होगा। हालिया बजट में आयकर कानून में एक संशोधन हुआ है, जिसके अनुसार यदि कंपनी छोटे वेंडरों को 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उस राशि को टैक्स के छूट के लिए नहीं दिखाया जा सकता और उस पर कर लगेगा। संशोधन की मंशा ठीक है, पर इसका असर नुकसानदेह हो सकता है। पहला, आयकर विभाग के डर से कुछ बड़ी कंपनियां छोटे व मझोले उद्यमों से खरीद बंद कर देंगी। इस क्षेत्र के अलावा होने वाली खरीद पर यह प्रावधान लागू नहीं होता। यह असर वैसा ही है, जैसा 2016 के मातृत्व अवकाश कानून के साथ हुआ था। यह कानून महिलाओं की मदद के लिए बना था, पर इससे उनके रोजगार की संभावनाएं सीमित हो गयीं। दूसरी गंभीर समस्या उक्त संशोधन से यह है कि इसमें एक ऑडिटर की जरूरत होगी, जो वित्त वर्ष के अंत में बकाया का लेखा-जोखा करे।

अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि नेता बदजुबानी करने लगें

योगेंद्र योगी

देश के विकास की बागडोर नेताओं के हाथ में है। देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति होने से उम्मीद यही की जाती है कि नेता देश को नई दशा-दिशा देंगे। देश और समाज के समक्ष अपने आचरण और व्यवहार से आदर्श पेश करेंगे। इसके विपरीत यदि नेता ही अपने जुबान पर लगाम नहीं रख पाएं तो देश के भले की उम्मीद नहीं की जा सकती। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि नेता बदजुबानी पर उतर आएं। ऐसे बेलगाम नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संयम और अनुशासन बरतने का क्या संदेश देंगे। आत्मानुशासन की बजाए नेताओं को कानून के जरिए संयत भाषा और आचरण से नियंत्रित किए जाने की कार्रवाई उनको आईना दिखाने वाली मानी जाएगी। अपशब्द कहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा और उससे गई संसद की सदस्यता से उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे। नेताओं को जुबान पर लगाम का सबक सिखाने के मामले में राहुल गांधी को मिली सजा मील का पत्थर साबित होगी। इससे कम से कम सार्वजनिक रूप से गरिमा के प्रतिकूल टिप्पणी करने की कीमत चुकाने से नेताओं में डर पैदा होगा। यह पहला मौका नहीं है जब किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को अदालत से मिली सजा और उसके बाद संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी हो। इससे पहले राजद के नेता लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता सहित कई नेताओं को विधानसभा और लोकसभा से सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। राहुल के सिवाय इन नेताओं को आपराधिक और दूसरे मामलों में जेल की सजा सुनाए जाने पर सदस्यता खोनी पड़ी। इसके विपरीत राहुल को एक जाति विशेष पर अपशब्द कहने के कारण सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। देश की विभिन्न अदालतों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर नेताओं के खिलाफ दर्जनों मानहानि और आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ भी करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस पर टिप्पणी करने पर कई मामले चल रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चौकीदार चोर है जैसी टिप्पणी करने पर वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में बगैर शर्त माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने इससे सीख लेने की बजाए अमर्यादित भाषा बोलना बंद नहीं किया। अदालत से बाहर भी राहुल ने इस तरह की अभद्रता करने पर अफसोस जाहिर नहीं किया। अब कांग्रेस इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाए हुए है। कांग्रेस इसे कर्नाटक चुनाव सहित आगामी चुनावों में मुद्दा बना रही है। इससे यही माना जाएगा कि कानून का सम्मान करने की बजाए आंखें दिखा कर सहानुभूति बटोरने के प्रयास से कांग्रेस देश में समस्याओं के असली मुद्दों से मुंह फेर रही है। राहुल से पहले भी अभद्र टिप्पणी करने पर कई नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस की इंदौर इकाई के सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष चन्द्रशेखर पटेल को पुलिस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नागपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पूर्व कांग्रेस जिला पदाधिकारी शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुसैन ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे। इसी तरह के आरोप में लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से सम्बद्ध मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के कई मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। जिला या राज्यस्तरीय नेता होने के कारण इन मामलों में की हुई कानूनी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय नहीं रही। परोक्ष तौर पर कांग्रेस के सर्वेसर्वा होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई की गूंज देशभर में है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से भड़की कांग्रेस देश भर में धरने-प्रदर्शन करके इसे चुनावी मुद्दा बना रही है।

चीन की गीदड़-भभकी से क्यों परेशान हों?

डॉ. रमेश ठाकुर

चीन ने अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जगहों का नाम बदलने का एक ऐसा शफूगा छोड़ा है जिसमें ना आवाज है और ना ही चिंगारियां? फिलहाल ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जब, उसने इन जगहों के नाम बदलने की कोशिश की हो, पूर्व में भी उसने ऐसी ओछी हरकत करके उकसाने का काम किया था। उसकी इस गीदड़ भभकी को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पर, सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। दुश्मन चाहें, कमजोर हो या ताकतवर हल्के में नहीं लेना चाहिए। केंद्र की खुफिया एजेंसियों और अरुणाचल प्रदेश की लोकल इंटेलिजेंस को पैनी निगरानी उन क्षेत्रों पर रखनी होगी, जिनका नाम बदलने का जिक्र किया गया है। सैन्य पहरा भी जरूरी है। क्योंकि यही वो भाग है जिस पर दुश्मन की कई दशकों से नजर है और जिसे हम अपना अभिन्न अंग बतलाते हैं।

चीन ने अपने सरकारी अखबार के जरिए जो ये विवादित बात कही है, उसके परिणाम दूरगामी भी हो सकते हैं। क्योंकि इस बार उनकी बकायदा मीटिंग में नाम तय किए गए हैं। जैसे विपक्ष सालों से आरोप लगाता आया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में घुस गया है। आज से दो वर्ष पूर्व यानी दिसंबर-2021 में भी चीन ने अरुणाचल के विभिन्न जगहों के नाम बदलने का कोरा झूठ बोला था। तब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि चाइना ऐसा करके हमें दिग्भ्रमित करना चाहता है। अपनी नापाक हरकतों से हमारी नजरें हटाना चाहता था। सोचने वाली बात है, हमसे हजारों किलोमीटर दूर पर बैठे लोग पहले से तय हमारे स्थानों के नाम बदलने की बात करते हैं। इसे उनके दिमाग का दिवालियापन ही कहा जाएगा। ऐसे तो हमारी सरकार भी दिल्ली में बैठकर शंघाई का नाम 'संघर्ष नगर' रख देगी, तो क्या उससे उसका नाम संघर्ष नगर हो जाएगा। नाम तो नहीं बदलेगा। पर, उपहास जरूर उड़ेगा, जैसा इस वक्त चीन का उड़ रहा है।

नाम-वाम बदलने का नया विवाद दरअसल है क्या? इसे आसान थ्योरी में अगर समझें तो इसे चीन की नापाक चाल ही कहेंगे। उसने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को

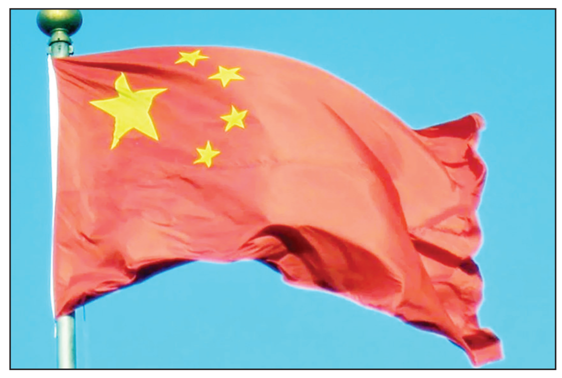

अपना हिस्सा बताकर करीब हमारे 11 अधिकृत स्थानों को अपना नाम दिया है। इसके लिए बाकायदा बीते रविवार को चीनी कैबिनेट की 'स्टेट काउंसिल मीटिंग' आयोजित हुई जिसमें ये सभी प्रस्ताव पारित हुए। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों को बिंदुवार तरीके से नए नाम रखे गए। क्योंकि इन नामों को पहले से उनके पास सटीक भौगोलिक जानकारियां हैं ही, जिन स्थानों के नाम बदलने की ये घोषणा हुई है उनमें दो रिहायशी इलाके हैं। पांच ऊँचे पर्वतों वाली चोटियां हैं। दो नदियां हैं और दो अन्य क्षेत्र हैं। दोनों नदियों का पानी दोनों ओर गिरता है। फिलहाल हमारे पास ये खबर अभी तक चीन सरकार के मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' के हवाले से आई है। अधिकृत तौर पर उनकी सरकार ने अभी कोई कोई सूचना नहीं दी है और ना ही ऐसे कोई प्रयास किए गए हैं।

गौरतलब है कि चीन ने बकायदा उन स्थानों के अधीनस्थ प्रशासनिक जिलों की श्रेणी भी सूचीबद्ध की है। जबकि, ऐसी ही एक हिमाकत 2017 में भी की थी, जब उन्होंने अरुणाचल के छह स्थानों को अपना बताया था। भारत सरकार ने हमेशा इन हरकतों का बिना कोई जवाब दिए प्रतिवाद किया है और करना भी चाहिए। ऐसे विवादों पर केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से मुखर नहीं होती। उनको पता है ये उनका मात्र चिढ़ाने वाला तरीका है। जब, कोई लिखित में चिट्ठी या कब्जे की सीधी कोशिशें होंगी तो उसका प्रतिकूल और माकूल उत्तर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में है। बैठक रविवार को हुई थी, दो-तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले की तरह सुरसुरी ही छोड़ी है जिसमें ना आवाज है और न तरंगें।

अभी कुछ महीने पूर्व की ही बात है। जब, चीन के इसी सरकारी अखबार के हवाले से ये झूठी खबर प्रकाशित हुई कि उन्होंने गलवान घाटी के आसपास से अपनी फोर्स हटाने का निर्णय ले लिया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी सेना हटाएंगे। दरअसल, ये उनका कोरा झूठ था, भारत सरकार को भ्रमित करने का ताकि इसके बाद भारत अपनी सेना हटाए और वह चुपके से रात के अंधेरे में धावा बोल दे। क्योंकि चीनी रात के अंधेरे में चोरी-चकारी और उल्टे सीधे कामों के माहिर होते हैं। देखिए ये बदला हुआ भारत है, अब यहां रात में भी चौकन्ने रहते हैं। हिंदुस्तान 1962 के मुकाबले 2023 में बहुत मजबूत खड़ा है। हुकूमत भी कठोर है जिसे चीन भलीभांति जानता और समझता भी है। वरना, अभी तक तो कोई ना कोई गड़बड़ी कर चुका होता? कुछ हरकतें की भी जिसका उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब भी मिला।

चीन को लग रहा है कि उनके इस निर्णय पर भारत सरकार में खलबली मचेगी, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं? क्योंकि केंद्र सरकार चीनी मसले पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। केंद्र सरकार अरुणाचल क्षेत्र पर आंच तक नहीं आने देना चाहती। 2017 में जब निर्वासित तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा हुई तब भी चीन ने हंगामा काटा था। चीन ने भारत सरकार पर खूब दबाव बनाया था ताकि भारत उनकी यात्रा रोक दें। यात्रा रोकने की बजाय भारत ने उलटे दलाई लामा की कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था में यात्रा को संपन्न कराया और उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में प्रोटोकॉल भी दिया। इससे चीन और आग बबूला हो गया। अंदर ही अंदर मन मसोसकर रह गया। उसी दौरान उनके विदेश उप-मंत्री का भारत दौरा था, उसने खुन्नस में आकर वह निरस्त कर दिया। चीन किसी भी सूरत में समूचे एशिया में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। इसके लिए वो प्रत्येक हथकंडे अपना रहा है।

बहरहाल, केंद्र सरकार चीन की प्रत्येक चाल को कुचलती आई है। नापाक हरकत करने का जरा भी मौका नहीं दे रही है। यही वजह है कि चीन जो भी कुछ कर रहा है, शंघाई में ही बैठकर कर रहा है। उसे पता है, मैदान में आकर उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। चीन ने भारत के खिलाफ नेपाल और पाकिस्तान को भी उकसा कर देख लिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तालिबानियों से भी मदद मांग ली, उन्होंने भी खाली हाथ लौटा दिया। कुल मिलाकर वह चारों तरफ से अब अकेला पड़ गया है। नेपाल-पाकिस्तान के बस की तो कुछ है नहीं, जो सीधे तौर पर वो भारत को कोई नुकसान पहुंचा सके। नेपाल की सत्ता में चीन का बढ़ता कदम आने वाले समय में नेपालियों के लिए ही भारी पड़ने वाला है। चीन नेपाल के साथ मिलकर हमें परेशान करने की फिराक में था। वहां भी उनकी दाल नहीं गली।

बहरहाल, भारत-चीन सीमा विवाद की एबीसीडी समझने की जरूरत है। 3500 किमी लंबी सीमा है जो तीन सेक्टरों में विभाजित है। अव्वल, पश्चिमी सेक्टर जो जम्मू-कश्मीर में 1597 क्षेत्रफल में फैला है। जहां, चीन का दखल नहीं है। दूसरा, मध्य सेक्टर है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझा सीमाओं से सटा हुआ है जिसकी अधिकृत लंबाई 545 किमी है। यहां, भी उसकी ज्यादा कोई दखलंदाजी सीधे तौर पर नहीं है। तीसरा, क्षेत्र जो पूर्व क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश से सटा बारीक-सा हिस्सा सिक्किम से लगा है जिसकी लंबाई 1346 किमी है, जिसे वह कब्जाना चाहता है। जबकि, अक्साई क्षेत्र ऐसा है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, जो कभी हमारा हुआ भी करता था। जिसे चीन ने 1962 युद्ध के बाद कब्जा लिया था। तभी से ये भाग उसके कब्जे में है। वहीं, पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, उसके पूरे भूभाग को चीन अपना बताता है, उस क्षेत्र में जितने भी भारतीय गांव-कस्बे बसे हैं उनका नाम बदल रहा है चीन। नया विवाद यहीं से शुरू हुआ है। जबकि, ऐसे हरकतें वो एकाध दफे नहीं, बल्कि बीते एक दशक में पांचवीं बार कर चुका है। आगे भी करेगा, ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार को भी करीब 600 किमी में फैले अक्साई क्षेत्र के नामों को बदलकर अपने नाम दे देने चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र का पुराना नक्शा आज भी हमारी हुकूमत के पास सुरक्षित है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

वज्रसूचिकापानषद् (भाग-01)

यह उपनिषद् सामवेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल 9 मन्त्र हैं। सर्वप्रथम चारों वर्णो में से ब्राह्मण की प्रधानता का उल्लेख किया गया तथा ब्राह्मण कौन है, इसके लिए कई प्रश्न किये गये। क्या ब्राह्मण जीव है? शरीर है, जाति है, ज्ञान है, कर्म है या धार्मिकता है ? इन सब सम्भावनाओं का निरसन कोई न कोई कारण बताकर कर दिया गया, अन्त में ब्राह्मण की परिभाषा बताते हुए उपनिषद्कार कहते हैं कि जो समस्त दोषों से रहित, अद्वितीय, आत्मतत्त्व से सम्पृक्त है, वह ब्राह्मण है। चूँकि आत्मतत्त्व सत्, चित्, आनन्द रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से सम्पन्न मनुष्य को ही (सच्चा) ब्राह्मण कहा जा सकता है।

अज्ञान नाशक, ज्ञानहीनों के दूषण, ज्ञान नेत्र वालों के भूषण रूप वज्रसूची उपनिषद् का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद वचन है और स्मृति में भी वर्णित है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण कौन है ? क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर है अथवा जाति अथवा कर्म अथवा ज्ञान अथवा धार्मिकता है। इस स्थिति में यदि सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण मानें (कि ब्राह्मण जीव है), तो यह सम्भव नहीं है; क्योंकि भूतकाल और भविष्यत्काल में अनेक जीव हुए हैं व होंगे। उन सबका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी स्व-स्व कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में, जीवों में एकत्व रहता है, इसलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्या शरीर ब्राह्मण (हो सकता है ? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चाण्डाल से लेकर सभी मानवों के शरीर एक जैसे ही अर्थात् पाञ्चभौतिक होते हैं, उनमें जरा-मरण, धर्म-अधर्म आदि सभी समान होते हैं। ब्राह्मण-गौर वर्ण, क्षत्रिय-रक्त वर्ण, वैश्य-पीत वर्ण और शूद्र-कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता तथा (यदि शरीर ब्राह्मण है तो) पिता, भाई के शरीर के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या आदि का दोष भी लग सकता है। अस्तु, शरीर का ब्राह्मण होना सम्भव नहीं है ।

क्या जाति ब्राह्मण है (अर्थात् ब्राह्मण कोई जाति है) ? नहीं, यह भी नहीं हो सकता; क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जन्तुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है जैसे मृगी से शृंगी ऋषि की, कुश से कौशिक की, जम्बूक से जाम्बूक की, वल्मीक (बाँबी) से वाल्मीकि की, मल्लाह (धीवर) कन्या (मत्स्यगन्धा) से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की।

क्रमशः...

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चिंगारी भड़काने वाले मंगल पांडे

अभिनय आकाश

ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़काने वाले बैरकपुर रेजीमेंट के सिपाही मंगल पांडे जिन्हें देश को आजाद कराने का पहला श्रेय दिया जाता है। उनकी आजादी की चिंगारी ने ही ब्रिटिश हुकूमत को इतना खौफजदा कर दिया कि निश्चित तारीख से दस दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34 वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री (बीएनआई) रेजिमेंट में एक सिपाही (सैनिक) के रूप में सेवा की। कारतूसों में लुब्रिकेंट के रूप में गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की खबरों के बाद उन्होंने नई पेश की गई एनफील्ड राइफल के ग्रीस्ड कारतूसों को दांतों से हटाने से इनकार कर दिया। 'मारो फिरंगियों को' का हुंकार देने के साथ ही मंगल पांडे ने सिपाहियों से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने के लिए कहा और हथियार उठा लिया था।

मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई, 1827 को

ब्रिटिश भारत के सीडेड एंड कॉनक्वेर्ड प्रोविंस (वर्तमान में उत्तर प्रदेश में) के बलिया गांव में हुआ था। मार्च 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट की 5वीं कंपनी में एक निजी सैनिक बन गए।

अंग्रेजों ने 1850 के दशक के मध्य में भारत में एक नई एनफील्ड राइफल पेश की और इसके कारतूस के सिरों को काटने के बाद ही हथियार में लोड किए जा सकते थे। अफवाहों का दौर शुरू हो गया कि कारतूस में इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट में गाय या सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुओं में गायों का मां का दर्जा दिया जाता है, जबकि मुसलमानों के लिए सूअर का मांस वर्जित है। इस वजह से भारतीय सिपाहियों में आक्रोश की भावना पैदा होने लगी। पांडे उस दौरान बैरकपुर के गैरीसन में तैनात थे। आस्था से हिंदू ब्राह्मण, पांडे भी इस मामले के बारे में जानकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को अपनी अस्वीकृति दिखाने का संकल्प लिया। आमतौर पर यह माना जाता है कि पांडे ने अपनी रेजिमेंट के अन्य सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने का प्रयास किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई।

29 मार्च, 1857 को बैरकपुर में तैनात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के एडजुटेंट इयुटेनेंट बॉघ को पता चला कि उनकी रेजिमेंट के कुछ सिपाही उत्तेजित अवस्था में हैं और एक मंगल पांडे बंदूक की कारतूस को लेकर अपने साथी को विद्रोह करने के लिए उकसा रहा है। 24 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे ने रेजीमेण्ट के अफ़सर एडजुटेंट इयुटेनेंट बॉघ पर हमला कर के उसे घायल कर दिया। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ़्तार करने का आदेश दिया पर ज़मीदार ने मना कर दिया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फ़ांसी दे दी गयी।

भाजपा के 'हनुमान' करेंगे देश की हर समस्या का समाधान

अतुल सिन्हा

प्रधानमंत्री मोदी या कहें कि उनकी बेहद मजबूत रिसर्च टीम किसी भी अवसर को भारतीय हिंदू संस्कृति और पौराणिक चरित्रों से जोड़ने में माहिर है। अब अगर हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने रामचरित मानस के किष्किंधा कांड की (चौपाई कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहीं होय तात तुम्ह पाहीं) का जिक्र किया तो वह अनायास ही नहीं था। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी को बने 44 साल हो गए और इन करीब साढ़े चार दशकों में भाजपा कहां से कहां पहुंच गई, यह दुनिया देख रही है। खासकर तब जब देश की सियासी संरचना के कुछ मूलभूत तत्व बहुत ही छिन्न-भिन्न हालत में नज़र आते हों और पिछले तीन दशकों से भारतीय राजनीति में कई नई धाराएं आती जातीं और बिखरती रही हों।

भाजपा जिस नए भारत की परिकल्पना के साथ देश पर राज करने आई है और जिस तरह अपने चाल, चरित्र और चेहरे से यह संदेश बार-बार देती है कि वह जो चाहेगी वही करेगी, जैसा चाहेगी वैसा देश बनाएगी, देश की संस्कृति की अपनी परिभाषा गढ़ेगी और यहां तक कि लोकतंत्र के भी अपने मायने बताएगी, उससे साफ है कि हनुमान जयंती पर इस चौपाई के जरिये खुद की तुलना हनुमान से करने के पीछे भी वही अवधारणा है। मोदी इस चौपाई का मतलब समझाते हुए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं और कहते भी हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान नहीं कर सकते और इसीलिए यही भाजपा की प्रेरणा भी है। यानी ऐसा कोई काम नहीं है जो भाजपा नहीं कर सकती।

किष्किंधा कांड की यह तीसरी चौपाई है। इसे पूरा पढ़ते हैं...

कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥
राम काज लगि तव अवतारा। सुनतहिं भयउ पर्वताकारा॥

इसका मतलब साफ है कि दुनिया में ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, जो तुमसे न हो सके और खासकर राम के किसी भी काम को करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान पर्वताकार हो गए।

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कोई बात यूं ही नहीं कहते। उन्होंने हनुमान जयंती के बहाने पार्टी के हर कार्यकर्ता को हनुमान बनने का हौसला दिया। यानी, राम की हर आज्ञा या हर इच्छा पूरी करने का संकल्प लेने वाले हनुमान बनने की नसीहत दी। जाहिर है आज के इस कलयुगी सियासी दौर में भी राम तो एक ही होगा, बेशक हनुमान या उनकी वानर सेना अपने विशाल और वृहद रूप में नज़र आनी चाहिए, जो अपने प्रभु के इशारे समझे और उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहे।

दरअसल हमारे पौराणिक पात्र बहुत मायने रखते हैं। तुलसीदास ने जब रामचरित मानस की रचना की, तब भी उन्होंने इसके हर दोहे, चौपाई, सोरठा या छंद के जरिये ये बात बताने की कोशिश की कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही, लेकिन वो जैसे-जैसे बढ़ते गए, उनका कारवां बनता गया। और अगर पवनपुत्र हनुमान न होते, तो शायद राम को भी आज मौजूदा स्वरूप में न माना जाता। यानी राम और हनुमान को परिकल्पना एक दूसरे के बगैर नहीं की जा सकती।

वैसे देखें तो किसी भी पार्टी के लिए, उसके कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आप अपनी रणनीति बनाते रहिए, अगर आपके पास कार्यकर्ताओं की ताकत नहीं है, तो आप उसे मजबूती से लागू भी नहीं कर सकते। भाजपा इन 43 सालों में अपनी इसी ताकत के साथ बढ़ती चली गई है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। अबतक 18 करोड़ सदस्यों वाली भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के सदस्यों की संख्या दो करोड़ से भी कम है। 1980 में बेशक भाजपा बनी हो, लेकिन इससे पहले भारतीय जनसंघ ने और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग-अलग संगठनों ने अपना जनाधार तैयार कर रखा था। बेशक राम मंदिर आंदोलन और लालकृष्ण आडवाणी की 1990 की रथयात्रा के बाद माहौल और बना और अयोध्या आंदोलन ने भाजपा को इतना मजबूत बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आते आते भाजपा के सदस्यों की संख्या करीब दो करोड़ पार कर चुकी थी और मोदी सरकार आने से पहले यह छह करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन पिछले नौ सालों में पार्टी ने जबरदस्त विस्तार किया और सदस्य संख्या छह से 18 करोड़ तक पहुंच गई, यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से भी दोगुनी।

लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि भाजपा के जबरदस्त विस्तार की वजह खुद कांग्रेस के भीतर की कमजोरियां रही हैं, साथ ही कांग्रेस और भाजपा विरोध के नाम पर तीसरे मोर्चे जैसी ताकतों का सामने आना, गठबंधन की राजनीति और सत्ता के लिए बेमेल तालमेल का खेल का भी भाजपा ने फायदा उठाया है। बावजूद इसके अब भी कांग्रेस के तमाम नेता मानते हैं कि बेशक भाजपा संख्या के लिहाज़ से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन जिस विचारधारा और हिंदू कट्टरवाद को लेकर वह आगे बढ़ती है वह इस देश की साझी संस्कृति को शायद बहुत दिनों तक कबूल नहीं होगा।

वहीं कम्युनिस्ट और समाजवादी खेमे के नेताओं का कहना है कि देश की जनता को बेशक लग रहा हो कि विकल्प का अभाव है या मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व कोई और नहीं दे सकता, लेकिन जो उसकी रोजमर्रा की मुश्किलें हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और सबसे बड़ी बात नफरत और असुरक्षा का माहौल है, उसे लेकर भीतर ही भीतर असंतोष की चिंगारी तो सुलग ही रही है। कांग्रेस समेत इन तमाम पार्टियों को अब भी लगता है कि 2024 में कुछ कमाल हो सकता है। वह तो यह भी मानते हैं कि कर्नाटक से ही इस बदलाव की शुरुआत हो जाएगी।

जमीनी हकीकत पर गौर करें, तो फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। यह बात कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी के नेता भी दबी जुबान से स्वीकारते हैं लेकिन यह बात वह खुल कर नहीं कर सकते। भाजपा के स्थापना दिवस पर मोदी ने जिस तरह के संदेश दिए और जो संकेत दिए हैं, उसके खास मायने हैं। खासकर तब जब पूरा देश हनुमान जयंती के रंग में रंगा है और हर ऐसे उत्सव और शोभायात्राओं के अपने सियासी मायने होते हों। अब सबकी निगाह भाजपा के राम और हनुमान पर है कि देखें ये 2024 में क्या गुल खिलाते हैं।

गांधी आज

लोक सेवक के लक्षण- सामान्य (भाग-02)

गतांक से आगे...

जनता या दूसरे साथी अथवा नेता या स्वयंसेवक मंडल से बाहर के कार्यकर्ता कृतघ्न हैं अथवा कार्य में विघ्नरूप हैं-जिस सेवक को बार-बार ऐसा प्रतीत होता हो कहना उसमें ही कोई भारी दोष है यह बात वह पक्की माने क्योंकि ऐसा अनुभव है, कि जनता साधारणतः कृतज्ञ ही नहीं बल्कि बड़ी उदारता से लोक सेवक की कद्र करनेवाली होती है। जनसेवक में नीचे लिखे गुण होने चाहिए- वह धार्मिक वृत्तिवाला होना चाहिए। अर्थात् उसे सत्याग्रह, सत्कर्म, सद्वाणी और सद्वर्तन में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। इसके लिए उसमें लगन, भूल होने की अवस्था में पश्चाताप और जनता का श्रेय है यह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। उसका चरित्र इतना विशुद्ध होना चाहिए कि स्त्रियाँ उसके पास निर्भय होकर जा सकें और लोगों को उसे स्त्रियों के पास जाने देने में संकोच न मालूम हो। उसका आर्थिक व्यवहार सर्वथा शुद्ध होना चाहिए। कितने ही लोग बड़ी रकमों में तो ईमानदार होते हैं, पर %दमड़ी-छदाम के चोर होते हैं। कितने पाई का हिसाब तो सही-सही देते हैं और बड़ी रकमों में गोलमाल करनेवाले होते हैं। लोक सेवक को इन दोनों आक्षेपों से परे होना चाहिए और अपनी मार्फत आई हुई पाई-पाई का उसे ठीक-ठीक हिसाब रखना चाहिए।

उसे सतत उद्योगी होना चाहिए। जो गपशप, फालतू निन्दा-स्तुति में अपना समय बिताता है वह सेवक कभी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। उसकी उद्योगशीलता ऐसी होनी चाहिए कि लोगों पर उसकी छाप बैठ सके। कार्य के समय -पालन की आदत उसे अवश्य होनी चाहिए। जिस लिए जो समय तय किया हो उसमें चूक न होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे सदैव नियमों का ठीक तौर से पालन करते रहना चाहिए। सुबह से रात तक की उसकी क्रिया घड़ी की सुई की भाँति यथाक्रम चलती होनी चाहिए। इसके सिवा अपनी संस्था के सिद्धांतों और नियमों का पालन उसे लगन के साथ करना और अपने प्रधान की आज्ञा का ठीक-ठीक पालन करने वाला होना चाहिए। जो आज्ञा-पालन करना नहीं जानता वह आज्ञा-पालन कराने की योग्यता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लोक-सेवक को अपने देह-गेह की चिन्ता ईश्वर को सौंपकर निर्भयता प्राप्त करनी चाहिए। लोक-सेवा के लिए अपने धन, प्राण, कुटुंब, सुख, सुविधा, स्वतंत्रता इत्यादि का त्याग करने की पहली ज़िम्मेदारी उसे अपने सिर ले लेनी चाहिए।

क्रमशः...

संक्षिप्त समाचार

सत्तीचौरा मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि की कामना

दुर्ग। मुख्यमंत्री ने दुर्ग विधानसभा के

गंजपारा में सत्तीचौरा स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और दुर्ग विधायक श्री अरूण वोरा सहित जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। गंजपारा स्थित सत्तीचौरा मंदिर का इतिहास स्थानीय लोगों से छिपा नहीं है। सत्तीचौरा मां दुर्गा मंदिर की स्थापना 2010 में हुई थी। मान्यता है की धार्मिक एवं शुभ कार्य करने से पहले माता में नारियल चढ़ाया जाता है। ज्ञातव्य है कि गंजपारा सत्तीचौरा में एक ऐसा चौरा है जहां पर एक महिला अपने आत्मशक्ति से अग्नि प्रज्जवलित कर सती हुई थी, उसके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गंजपारा में सतीचौरा में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई।

ईडी का तर्क पूरा, 11 को होगी सौम्या चौरसिया के जमानत पर सुनवाई

बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत के लिए 11 अप्रैल 2023 तक इंतजार करना होगा क्योंकि जमानत पर सुनवाई इसी दिन होगी। ईडी ने जमानत के विरोध में गुरुवार को अपना तर्क पेश कर दिया है। उल्लेखनीय हैं कि पिछले 3 तारीखों में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया था कि सौम्या के ठिकानों पर ईडी ने तीन बार छापे मारे, बैंक लॉकर और बैंक खातों की जांच की गई लेकिन ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईडी के मामले में उन्हें जमानत दी जानी है जो महिला, वृद्ध या वयस्क हैं। चौरसिया के पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई है। ईडी की ओर से गुरुवार को जमानत के विरोध में तर्क पूरे हो गया और उसकी ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता डॉ सौरभ पांडे ने कहा कि डायरी में एंट्री की गई तारीख और निवेश की तारीख आपस में मिल रही है, स्वतंत्र जांच से यह स्थापित भी हुआ है। निवेश, विक्रय पत्र अनुबंध आदि का भी ईडी ने जिक्र किया है।

हवाई हमले में नक्सलियों को बनाया निशाना : माओवादी प्रवक्ता

बीजापुर। बीजापुर में नक्सलियों को निशाना बनाकर बीजापुर और सुकमा की सीमा पर हवाई हमला किया गया। माओवादियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी कर बमबारी की जानकारी दी। माओवादी प्रवक्ता ने दावा किया की हवाई हमले में नक्सलियों को निशाना बनाया गया है। दक्षिण बस्तर के पामेड़ इलाके के भट्टिगुड़ा,कवरगट्टा,मीनागट्टा और जब्बागट्टा इलाके में सुबह 6 बजे से ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बमबारी जारी है। माओवादी नेता ने केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री अमित शाह के दौरे को इस हमले के लिए जिम्मेदार बताया।

प्रेमलता नागवंशी एक दिवसीय मानस सम्मेलन में शामिल हुई

नगरी। ग्राम मेचका में श्री हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा पर श्री हनुमान जी का मंदिर स्थापना कार्यक्रम व एक दिवसीय मानस सम्मेलन में भाजपा जिला मंत्री व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमलता नागवंशी शामिल हुईं। उन्होंने ग्रामवासियों व वरिष्ठों के साथ श्री हनुमान जी का पूजन किया तथा वहाँ चल रहे मानस गान को सुना। इस अवसर पर उनके साथ महिला मोर्चा मंडल नगरी अध्यक्ष सुलोचना साहू, मंडल कोषाध्यक्ष महेश साहू, कैलाश साहू, भरत माँझी, जीवन नाग, लव साहू, सितन साहू व ग्रामवासी भारी संख्या में उपस्थित रहे।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोरबा प्रवास 8 और 9 अप्रैल को

कोरबा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री संजय अग्रवाल 8 और 9 अप्रैल को कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे 8 अप्रैल को प्रात: 10:30 बजे बिलासपुर से प्रस्थान कर दोपहर साढ़े 12 बजे कोरबा पहुंचेंगे। अपरान्ह तीन बजे कोरबा से प्रस्थान कर 03:30 बजे सतरेंगा पहुंचेंगे। वे 09 अप्रैल को प्रात: 11 बजे सतरेंगा से बिलासपुर के प्रस्थान करेंगे।

संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग का कोरबा प्रवास 19 अप्रैल को

कोरबा। बिलासपुर संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग 19 अप्रैल को एक दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहेंगे। वे प्रात: 08:30 बजे बिलासपुर से पोड़ी-उपरोड़ा कोरबा के लिए प्रस्थान कर प्रात: 11 से 12 बजे तक तहसील एवं एसडीम कार्यालय पोड़ी-उपरोड़ा का निरीक्षण करेंगे। संभागायुक्त दोपहर 12 से 01:30 बजे तक जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेंगे।

मोदी प्रदेश की तारीफ कर रहे और बीजेपी नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे : बघेल

रायपुर। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 13 तारीख का उन्होंने समय दिया है। जैसा सरगांव में कार्यक्रम किया गया था, वैसा ही जगदलपुर में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग में बड़ा अंतर आया है।पहले बस्तर में जितने लोग गोलियों से शहीद होते थे, उससे ज्यादा लोग मलेरिया की बीमारी से ग्रस्त होते थे, लेकिन अब बेहतर व्यवस्था होने की वजह से यह सुनने को नहीं मिलता। ये बातें उन्होंने भेंट मुलाकात के लिए दुर्ग जिला रवाना होने से पहले कहीं।

उन्होंने कहा कि जो जांच पहले महंगी हुआ करती थी, उसका अब मुफ्त इलाज हो रहा है। सरकार की कई योजनाएं जो स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही है उसका लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पर कहा कि जो सही काम है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नीति आयोग की तारीफ उन्होंने की है।

हमारे 10 चिन्हित जिले थे जिन्हे पिछड़ा माना गया था। उन जिलों में भी बहुत सारी उपलब्धियां हुई है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो ज्ञापन आया था, उसमे आवास गैस सिलेंडर और नल जल योजना की संख्या की जिक्र किया गया था, इधर बीजेपी के लोग इन सभी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह तो प्रधानमंत्री ने लिखा है की छत्तीसगढ़ में 17 लाख लोगों को नल-जल मिल गया है। 34 लाख लोगों को आवास मिला है, 35 लाख लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं। तो ये उपलब्धि ही बता रहे हैं जो की राज्य सरकार की उपलब्धि है।

...तो बंद हो जाएंगी ये योजनाएं

सीएम ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ बीजेपी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, भाजपा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को डबल टारगेट किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वे टारगेट कुछ भी करें, लेकिन भाजपा के लोग भी अब जान चुके हैं कि भाजपा की सरकार अगर गलती से भी बन गई, तो धान 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाएगा। 9 हजार रुपए प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं मिलेगी। अनेकों योजनाएं बंद हो जाएंगी। वे सब जान रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गलती से भी नही आएगी। और भाजपा के लोग यह जानते हैं।

छग प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने भरी हुंकार

5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया आंदोलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सीएचओ संघ के प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रदेश के 2500 संविदा सीएचओ कर्मचारियों ने नया रायपुर के तुता धरना स्थल पर अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि हम अपने अधिकारों की मांग के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार हैं, अन्य प्रदेशों में भारत सरकार के वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। मगर हमारे राज्य के सीएचओ कर्मचारी इन लाभों से वंचित हैं, जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। संगठन के आमन्त्रण पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से अलोक मिश्रा और रविन्द्र तिवारी एवं आल इंडिया एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में से सौरव सिंह, (राष्ट्रिय संगठन राज्य अध्यक्ष) एवं अंकिता वरवडे (राष्ट्रिय संयुक्त सचिव) द्वारा सी.एच.ओ. छत्तीसगढ़ संघ की मांगों को लेकर पूर्ण समर्थन किया गया। दोनों संघों के प्रतिनिधियों ने भरोशा दिलाया कि आपकी जायज मांगों के लिए सरकार से हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़े। हम

आपके हर कदम पर साथ हैं।

स्वास्थ्य अधिकारी संघ की ये हैं मांगें

1. कर्मचारियों के नियमितिकरण होने तक समस्त कर्मचारियों को 62 वर्ष नौकरी की सुरक्षा मिले। 2. भारत सरकार के वित्तीय दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिमाह 25000 रु. वेतन एव 15000 रु. कार्य आधारित वेतन का पालन हो। 3. कर्मचारियों को उनके गृह जिला में स्थानान्तरण के लिए सुविधा प्रदान की जाए। 4. मानव संसाधन निधि 2018 एवं कर्मचारी भविष्य निधि के नियमानुसार ईपीएफ का लाभ मिले। 5. जिले स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके सम्बंधित अधिकारियों ने मानसिक एवं आर्थिक उत्पीडन करने के विरोध में सबूतों के साथ 6 माह पूर्व एमडीएनएचएम को ज्ञापन दिया गया था, जिस पर कार्यवाही की मांग की गई।

श्रम मंत्री ने 22 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

रायपुर। नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने नगर पालिका आरंग में 22 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मंत्री डॉ. डहरिया का आरंग मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम मितानिन बहनों ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर शाल एवं श्रीफल भेंटकर आत्मीय स्वागत किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या फिर बिजली, पानी, सड़क की मांग की बात सभी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाजों के द्वारा सम्मान किए जाने पर मंत्री डॉ. डहरिया ने उपस्थित जनों का आभार जताया। इस अवसर पर मंत्री डॉ. डहरिया ने 20 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाली मितानिन भवन का भूमिपूजन और किचन शेड निर्माण हेतु 05 लाख रूपये की घोषणा भी की। जिसमें 3 करोड़ 57 लाख रूपये की लागत वाले नये पालिका भवन का लोकार्पण किया एवं विभिन्न समाज के सामुदायिक भवनों सहित 8 करोड़ 34

लाख रूपये के कुल 21 कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही 14 करोड़ 51 लाख रूपये के 131 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष जनपद पंचायत आरंग, श्री खिलेश्वर देवांगन, चन्द्रशेखर चन्द्राकर, द्वारिका साहू, देवनाथ साहू, राशि त्रिभुवन महिलांग, नरसिंग साहू, कोमल सिंह साहू, भारती देवांगन, शरद गुप्ता, दीपक चन्द्राकर, धनेश्वरी खिलवान निषाद, राममोहन लोधी, समीर गोरी, दीक्षा सूरज सोनकर, ममता जितेन्द्र शर्मा, सीमा नरेन्द्र लोधी, सुरज लोधी, ध्रुव कुमार मिर्धा, मंगलमूर्ति अग्रवाल, गणेश बांधे, उपेन्द्र साहू, राजेश्वरी साहू, भरत लोधी, गीता साहू, नंदकुमार यादव, के.के. चन्द्राकर, चन्द्रकला साहू, अनिल गुप्ता, तुलसी भाई पटेल, निर्मला साहू, मनमोहन गुप्ता, सजल चन्द्राकर, मनीष चन्द्राकर, मंजू चन्द्राकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विभिन्न समाज के पदाधिकारी एवं नगरवासी उपस्थित थे।

जीपी सिंह की क्रिमिनल रिट पिटीशन हाईकोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर। एक व्यापारी ने भयादोहन कर 20 लाख रुपये वसूल करने को लेकर निलंबित एडिशनल डीजी जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करने के बाद जीपी सिंह द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पिटीशन को खारिज कर दी है।

सिंह के खिलाफ 2021 में भिलाई, दुर्ग के एक व्यापारी ने स्मृतिनगर पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें व्यापारी ने कहा था कि तत्कालीन आईजी जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी थी। व्यापारी, उसकी पत्नी और परिजनों के खिलाफ पार्टनर की ओर से की गई शिकायत को कमजोर करने के नाम पर एक करोड़ रुपये की मांग सिंह ने की थी। एडवांस के तौर पर उन्होंने

20 लाख रुपये लिए। शिकायतकर्ता व्यापारी का अपने पार्टनर से लेन-देन का विवाद था। सिंह ने इस एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत झूठी है। कोर्ट ने इस पर व्यापारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दोनों पक्षों तथा शासन का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पिटिशन खारिज कर दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मा जयंती में की शिरकत, भूपेश सरकार पर बोला हमला

पेंड्रा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने एक दिवसीय दौरे पर पेंड्रा पहुंचे, जहां पर वे पेंड्रा के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में आयोजित माँ कर्मा जयंती में शामिल हुए। साव ने कहा साहू समाज इसे स्नेह सम्मेलन की तरह हर साल मनाता है। साथ ही उन्होंने रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश और जिले को लेकर चर्चा की जिसमे उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है।

अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बृहस्पति सिंह के थप्पड़ वाले सवाल पर छत्तीसगढ़ में कानून की स्थिति को लेकर कहा कि संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी कर्मचारी के साथ ऐसा करता है यह दुर्भाग्य की बात है। साव ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्होंने पिछड़ा समाज को लेकर जो टिप्पणी की थी उस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट के बार बार कहने पर भी राहुल गांधी ने माफी नही मांगी वो अहंकार में रहे अंतत: मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद से जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। सत्ता संघर्ष से जनता को नुकसान हो रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नारायण चंदेल को लिखी चिट्ठी पर अरुण साव ने कहां की छत्तीसगढ़ बनाने से लेकर छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचाएं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की राज्य महिला उद्यमिता नीति

- **महिला समूहों, उद्यमियों, व्यवसायियों एवं स्टार्टअप का तेजी से होगा विकास**
- **विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय में महिला उद्यमियों को दिया जाएगा वित्तीय सहायता**

रायपुर। महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, विकास उतनी ही तेजी से होगा। छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं के निर्माण के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही है। इसके साथ ही स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौठानों, वनोपज संग्रहण सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व एवं एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोडने् के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए सटार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा।

राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रूपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए तक ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। इस नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन, विस्तारीकरण, शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। उद्यम में किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30-55 प्रतिशत तक यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रूपए तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, उद्यमों के लिए प्राप्त किए गए सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर 45 से 70 प्रतिशत, अधिकतम राशि 15 से 60 लाख रूपए तक ब्याज अनुदान, नए उद्यमों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रूपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दिनांक से 6 से 16 वर्षों तक, विद्युत शुल्क से छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 से 12 वर्षों तक पूर्ण छूट और उक्त के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट, परिवहन अनुदान, मण्डी शुल्क से छूट, किराया अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रुप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।

शहरी बस्तियों में और बढेंगी इलाज की सुविधाएं

नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओं की हुई समीक्षा

- **भवन अनुज्ञा, नल कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गुमास्ता, लायसेंस आदि कार्य समय-सीमा में किए जाए : मुख्य सचिव**

रायपुर। छत्तीसगढ़ की शहरी बस्तियों में रहने वाले गरीब तबकों को अब और भी अधिक आसानी से इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में मोबाइल मेडिकल यूनिट की संख्या 120 से बढ़ाकर 150 की जा रही है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को शहरी गरीबों के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर मोबाइल यूनिटों के माध्यम से चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगरीय प्रशासन विभाग

की सेवाएं तत्परता से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि भवन अनुज्ञा, नल कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गुमास्ता, लायसेंस आदि कार्य समय-सीमा में किए जाए।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि शहरों में बनाए गए कृष्ण कुंज की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। बारिश से पूर्व कृष्ण कुंज में पौधे लगाए जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में बनाए गए गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट और गोबर से पेंट बनाने की इकाईयों की जानकारी ली और गौठानों में रोजगारमूलक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मितान योजना की मॉनिटरिंग की जाए। अधिकारियों ने बताया कि शहरी लोगों को शासकीय कामकाज के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए मितान योजना को भी विस्तारित करने की योजना है। बैठक में गोबर पेंट का उपयोग, अवैध निर्माणों का नियमितीकरण, व्यवसायिक भूखण्डों का विकास सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव श्री अयाज तम्बोली, संचालक नगरीय प्रशासन श्री आर.एक्का सहित नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन की संख्या 120 से बढ़कर 150 हो जाएगी। इस योजना में अब तक करीब 44 लाख 37 हजार से ज्यादा मरीजों का उपचार, 38 लाख मरीजों को निशुल्क दवाओं का वितरण और 11 लाख मरीजों को विभिन्न प्रकार का पैथालॉजी टेस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से 68 हजार 723 शासकीय दस्तावेज नागरिकों को उनके घर पर पहुंचाए गए है। मितान योजना के तहत करीब 78 हजार से अधिक लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर प्राप्त करने के लिए अपायमेंट बुक कराया गया है। श्री धनवन्तरी मेडिकल स्टोर्स योजना के तहत राज्य में 195 धनवन्तरी मेडिकल स्टोर्स संचालित हैं। इन स्टोर के माध्यम से लोगों को कम दामों में उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

जनता के बीच जाएंगे भाजपा के सभी मोर्चा- नितिन नबीन

रावण भी अपनी जनता के लिए कुछ काम करता था, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं किया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने सभी मोर्चों के प्रभारियों, अध्यक्षों व महामंत्रियों की की बैठक ली। बैठक में मोर्चा पदाधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्रमों और कार्य योजना से प्रदेश सह प्रभारी श्री नबीन को अवगत कराया। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय,प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप,ओपी चौधरी सभी मोर्चा के प्रभारी ,अध्यक्ष और महामंत्री आदि उपस्थित थे।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सभी मोर्चा अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न वर्गों के बीच जाएंगे। किसान मोर्चा किसानों को बतायेगा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं दी हैं। मोदी जी किसानों की बेहतरी के फैसले करते हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाकर बेरोजगारी भत्ता इत्यादि विषयो पर भूपेश बघेल सरकार की धोखेबाजी को तथ्यों के साथ बतायेगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा तेंदूपत्ता के मुद्दे पर वनवासियों के बीच होगा। महिला मोर्चा शराबबंदी, स्वयंसहायता समूह से किये धोखाधड़ी के मामलों में महिलाओं के साथ है और महिलाओं के हक में संघर्ष कर रहा है। महिला मोर्चा अपने कार्यक्षेत्र के विषयों पर महिलाओं के बीच जाएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा सहित सभी मोर्चा जनता के बीच जाएंगे। भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चिट्ठी पर कहा कि वे पहले अपने मंत्री टीएस सिंहदेव की चिट्ठी का जवाब दें। उन्होंने कहा कि रामराज्य सुशासन का प्रतीक है। रावण राज अन्याय का। फिर भी रावण अपनी जनता के लिए कुछ काम करता था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार चेहरा या जाति देखकर योजना नहीं बनाती। समान रूप से सभी के हित में योजनाओं का लाभ मिलता है। देश के सभी किसानों को पैसा दे रही है। सभी गरीबों को पक्का मकान दे रही है। अल्पसंख्यक वर्ग को समानता के साथ मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

मोर्चों के लिए कार्यक्रम तय किए गए

ज्ञातव्य है कि पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से आगामी 14 अप्रैल तक मोर्चों के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत चिकित्सा शिविर, करियर काउंसलिंग, बस्तियों में सह भोज और स्वच्छता के कार्यक्रम रखेगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा 8 अप्रैल को जनजातीय युवकों को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत सम्मेलनों के माध्यम से जागरूक कर रोजगार संबंधी योजनाओं से अवगत कराएगा और सिकलसेल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करेगा। किसान मोर्चा द्वारा 9 अप्रैल को प्राकृतिक खेती पर जन जागरण अभियान तथा श्रीअन्न योजना के लिए शहरी क्षेत्रों में जन जागरण के लिए पैदल मार्च किया जाएगा। 10 अप्रैल को महिला मोर्चा द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ सह भोज का कार्यक्रम रखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाई जाएगी, 12 अप्रैल को चिकित्सा व स्वच्छता शिविर तथा 13 अप्रैल को जलाशयों की सफाई व वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति मोर्चा बाबासाहब डॉ. भीमराव

शराबबंदी: मुख्यमंत्री का इंकार-भाजपा का प्रहार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल का अहम बयान सामने आया है। भेंट मुलाकात के दौरान सीएम बघेल ने यह स्पष्ट किया है कि पैसा लोगों की जान से बढ़कर नहीं है, लेकिन लोगों की जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं कर सकते. पहले लोगों को शराब पीना बंद करना होगा. दूसरी किस्म का जो नशा है, उसे भी छोड़ना होगा. सरकार को सभी तरह का नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है. सीएम के इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीति गरमाने के आसार हैं।

भेंट मुलाकात के दौरान एक महिला ने सीएम से कहा कि शराब बंद कर दें. इससे काफी नुकसान हो रहा है. व्यक्ति शराब पीकर मारपीट तो करता ही है, हिंसा भी फैलाता है. और पैसे की बर्बादी भी होती है. शरीर को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर सीएम बघेल ने कहा कि मैं शराब एक मिनट में बंद कर सकता हूं. अभी आदेश करूंगा और शराब की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन पहले कसम खाओ कि कोई शराब ना पिए. शराब पीना बंद कर दीजिए मुझे मेरी जनता से ज्यादा कीमत और पैसा शराब का नहीं हो सकता. सीएम ने कहा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ज्यादा कीमती है, लेकिन लॉकडाउन के समय में रायपुर में एक व्यक्ति सेनिटाइजर पीकर मर गया. शराबबंदी होने पर लोग जहरीली शराब पीते हैं और मर भी जाते हैं।

मुकरने वाले मुख्यमंत्री -कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था और उस घोषणा पत्र में लिखा था कि प्रदेश में पूर्णरूप से शराबबंदी की जाएगी। आज लगभग साढ़े चार वर्ष का समय बीत चुका है और कुछ दिनों के बाद आचार सहिता भी लग जाएगी लेकिन आज तक शराबबंदी नहीं हुई। उन्होंने कह कि कांग्रेस ने शराबबंदी के नाम पर जो कमेटी बनाई गयी महज एक जनता को छलने व दिखावे के लिये बनाई गयी थी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई गयी कमेटियां कई प्रदेशों में गई लेकिन उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई इसका मुख्य कारण वादाखिलाफी है

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम....

देश में नरेंद्र मोदी से अडानी के क्या रिश्ते हैं यह पूछने का मसला अब राहुल गाँधी को दो साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता रद्ध होने से लेकर नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता तक पहुंच गया है ।राहुल ने लोकसभा में मोदी-अडानी को निशाने पर लिया था,उसके बाद सूरत की कोर्ट से उन्हें कर्नाटक में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने पर अधिकतम 2साल की सजा देना ,संसद की सदस्यता समाप्त करना ,बंगला खाली करने का नोटिस, सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल को जमानत,प्रियंका गाँधी सहित 3 कॉंग्रेसी सीएम आदि के साथ सूरत कोर्ट में जाने को लेकर चर्चा जारी है वहीं नरेंद्र मोदी की डिग्री देखने के नाम पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 25 हजार का जुर्माना भी चर्चा में है ।दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी

थी ।गुजरात विश्वविद्यालय ने देने से मना कर दिया था तो केंद्रीय सूचना आयोग ने डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश दिया था इस पर विवि ने आयोग के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी ।उच्च न्यायालय ने आदेश रद्द ही नहीं किया बल्कि केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। यह निर्णय भी चर्चा में है। दरअसल चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी को अपने हलफनामे में डिग्री वगैरह की जानकारी देनी होती है और गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है। फिर किसी जनप्रतिनिधि की डिग्री मांगना अपराध कब से हुआ और इसे छुपाया क्यों जा रहा है। दूसरी बात,लोकतंत्र पारदर्शिता का दूसरा नाम है ।कानूनी तौर पर अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है या किसी पद पर रह सकता है ।जब ये कानून बना था तब पूरा भारत साक्षर नहीं था। कोई जन- प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है या नहीं,ये जानना जनता का अधिकार है। जनता से झूठ बोलना भी अपराध है। वैसे भी अमित शाह और अरुण जेटली,मोदी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सार्वजनिक कर चुके हैं जो कथित रूप से गुजरात यूनिवर्सिटी की है ।यूनिवर्सिटी को इसका सत्यापन करने में क्या परेशानी है ।या कम से कम यूनिवार्सिटी यही बता दे कि उसने यह विषय में दुनिया के एक ही छात्र को क्यों पढ़ाया ।वैसे नरेंद्र मोदी एक भाषण में यह कहते सुने जा सकते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं ।अगर वे कम पढ़े लिखे हैं तो भी तारीफ ही होगी कि कम पढ़ा लिखा आदमी सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा है ।अब तो उनकी वायरल डिग्री में यूनिवर्सिटी की दो अलग अलग स्पेलिंग की भी चर्चा तेज है, क्या कोई यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी गलती संभव है।

जमीन बेचा तो बाबा को हाईकोर्ट का नोटिस

पूर्वजों द्वारा दान करने, फिर अविभाजित मप्र के समय एक कलेक्टर द्वारा उसे सिंहदेव परिवार को वापसी का मामला छ्ग में भाजपा सरकार के समय चर्चा में आया था तब डॉ रमनसिंह सीएम थे और टीएस बाबा नेता प्रतिपक्ष थे ।पर

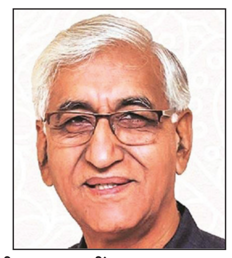

शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ... अब मामला छ्ग हाईकोर्ट पहुंच गया है ।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंह देव की तकलीफ और बढ़ा दी है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद छग की सियासत भी गर्माने लगी है ।बता दें कि मामला एक सार्वजनिक तालाब को काटकर उसे टुकड़ों में बेचने से जुड़ा हुआ है। अगर नोटिस की माने तो 11 अप्रैल से पहले व्यक्तिगत तौर पर टी एस सिंहदेव को उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए है ।पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली तनु नीर समिति द्वारा हाईकोर्ट में टीएस सिंहदेव के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में सिंहदेव के खिलाफ तालाब को पाटकर जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है ।मामला शहर के बीचों बीच स्थित 52.06 एकड़ में फैले शिव सागर मौलवी बांध की जमीन का है ।इसकी जमीन टीएस सिंहदेव के नाम पर है। तरू नीर समिति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में 20 मार्च को याचिका दाखिल किया था ।मामले में हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी किया है।

अवस्थी को ओएसडी बनाने के मायने

उप्र के मूल निवासी तथा छ्ग में आईपीएस प्रशिक्षण से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी सम्हालने वाले दुर्गेश माधव अवस्थी को सेवानिवृति के बाद छ्ग की भूपेश सरकार ने पुलिस मुख्यालय में ओएसडी का पद सृजित कर एक साल के लिये संविदा नियुक्ति दे दी है। अविभाजित मप्र से छ्ग की जोगी,डॉ रमन और भूपेश सरकार में महत्वपूर्ण पदों में रहने वाले अवस्थी फील्ड तथा पुलिस मुख्यालय में कई जिम्मेदारी सम्हाल चुके हैं ।वे मप्र और छ्ग में करीब 7 साल खुफिया विभाग में पदस्थापना का रिकार्ड बना चुके हैं। बहरहाल बतौर ओएसडी उन्हें क्या अधिकार रहेगा यह अभी तय नहीं है।

8 जिलों में प्रमोटी डीऍम तो 5 में डीआईजी हैं एसपी

छत्तीसगढ़ में 33जिलों में 25 में सीधे आईएएस अफसर कलेक्टर पदस्थ हैँ तो मात्र 8 जिलों में ही प्रमोटी आईएएस को कलेक्टर बनाया गया है। राजनांदगाव,रायगढ़, बालोद,कबीरधाम, गौरेला-पेंड्रारोड,सारंगढ़,सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रमोटी अफसर अभी पदस्थ हैं पर विस चुनाव के पहले जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे और प्रमोटी अफसरों को अधिक जिलों का प्रभार दिया जाएगा यह तय है ।क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है ।सवाल यह उठ रहा है कि करीब डेढ़ दर्जन कलेक्टर पिछले साल जून 22 में ही बदले गये थे,2 माह बाद ही उन्हें एक साल पूरे होंगे तो कुछ कलेक्टर को तो 6से 9 माह ही अभी जिलों में हुए है, इधर कुछ एसपी को भी बदलना तय है करीब 6 को तो 2साल से अधिक समय हो गया है उसमे भी 5 तो डीआईजी पदोन्नत हो चुके हैं, एक का नाम तो ईडी की चार्जशीट में भी है। वैसे आगामी विस चुनाव में पदस्थापना के चलते ही तबादला आदेश जारी होने में देर हो रही है।

और अब बस....

- भाजपा की बड़ी नेत्री ने थप्पड़ मारा था वो वह चुनाव हार गईं थीं,अब एक कॉंग्रेसी विधायक ने थप्पड़ मारा है।
- शेखर तिग्गा ने डीआईजी जेल का कार्यभार सम्हाल लिया है ।छ्ग बनने के बाद डॉ के के गुप्ता के बाद तिग्गा दूसरे विभागीय डीआईजी बने हैं।
- किस बड़े जिला के कलेक्टर से सत्ता पक्ष के लोग भी नाराज हैं और विपक्ष के लोग भी।
- आईजी स्तर पर भी मामूली फेरबदल की चर्चा तेज है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

चिट्ठी लिखने की बजाय चिट्ठियों का जवाब दें मुख्यमंत्री- चौधरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि दरअसल साढ़े 4 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों के लिए कुछ भी कर पाने में पूरी तरह विफल रहे हैं इसलिए बार-बार ब्लेम गेम करके केन्द्र को चिट्ठी लिखना उनकी आदत में शुमार हो गया है। मुख्यमंत्री के पास जनता को अपने 4:30 वर्ष की उपलब्धियों बताने के नाम पर कुछ नहीं है इसलिए वे सब बात को घुमा फिरा कर केंद्र पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिख रहे हैं पर पहले जनता जानना चाहती है कि श्री टी एस सिहदेव जी ने जो आप को पत्र लिखा था उसका जवाब क्या आपने टी एस सिंह देव जी को दे दिया ? क्योंकि अगर आपने सही जवाब दिया होता तो उनका इस्तीफा वापस हो गया होता। और आवासहीनों को आवास मिलना प्रारंभ हो गया होता। आप के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा कलेक्टर के भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए उसके खिलाफ पत्र लिखा था क्या आपने उसका जवाब दे दिया ? अगर आपने जवाब दिया होता तो अब तक भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हो गई होती।

मोदी राज में महंगाई चरम पर वस्तुओं के दाम दुगुने हो गये - मोहन मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि महंगी गैस, महंगा तेल, थोक और खुदरा महंगाई आजादी के बाद सर्वोच्च शिखर पर है, सिर्फ सत्ता की भूख में मोदी सरकार आम जनता की कमर तोड़ रही है, फिर भी महंगाई से देशवासियों को लूटने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रही है। पेट्रोल-डीजल 100 के पार, रसोई गैस 1177, खाने का तेल 200 के पार। आम जनता बेबस और लाचार है पर मोदी सरकार केवल अपने चांद पूंजीपति मित्रों के मुनाफे की सोच रही है। मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी विगत 7 साल में 258 परसेंट बढ़ाया है और डीजल पर 820 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इन तमाम आंकड़ों के बावजूद मोदी सरकार द्वारा महंगाई को झूठलाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि महंगाई को काबू करना मोदी सरकार के बस में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है। देश की जीडीपी 8.2 से गिरकर 5.7 हो गयी है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ मॉडल का लोहा मोदी सरकार भी मानने लगी है

रायपुर। विभिन्न योजनाओं में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के बेहतर क्रियान्वयन का लोहा अब मोदी सरकार भी मानने लगी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में लागू की गयी केंद्रीय योजनाओं की सफल क्रियान्वयन का विज्ञापन भी प्रकाशित करवाया है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में लिखा गया है-माँ की उचित देखभाल-प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना से छत्तीसगढ़ में 7 लाख से अधिक माताओं को मिली बेहतर देखभाल,कठिनाईयों को दूर भगाया, महिलाओं का सम्मान वापस दिलाया-छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बने लगभग 34 लाख से अधिक शौचालय, महिलाओं के लिये सरल हुआ जीवन,जीवन को बेहतर बनाया, सुविधा से मन मुस्कुराया-प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन से छत्तीसगढ़ में 17 लाख से अधिक घरों में नल से जल हुआ सुलभ। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि इसके पहले पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क के बेहतर क्रियान्वयन के लिये ट्वीट भी कर चुके है। राज्य में लागू होने वाली हर योजना को केंद्र सरकार की तारीफ मिल चुकी है।

शराबबंदी की बात पर जनता से वचन मांग रहे भूपेश बघेल

रायपुर। शराबबंदी के लिए जनता से शराब न पीने का वचन मांग रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसा पलटू मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है जो साफ साफ अपने वादे से मुकर जाए। यही भूपेश बघेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब उन्होंने जन घोषणापत्र में कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। बृजमोहन ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि केवल अवैध कमाई करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए आज लोगों के साथ भूपेश बघेल और उनकी कांग्रेस सरकार विश्वासघात कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं ने कांग्रेस को इसलिए वोट किया था क्योंकि भूपेश बघेल ने शराबबंदी का वादा किया था। अब जनता से ही शराब न पीने की कसम लेना तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में विशेष रुप से महिला मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। इसका बदला 2023 के चुनाव में जनता लेगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से जनता की जान जोखिम में डालना जैसी बाते मुख्यमंत्री का करना बेहद दुखद है। शराबबंदी का वादा तो जनता से पूछ कर किया नहीं था। क्या तब उनको परिस्थितियां नहीं मालूम थी ? उन्होंने कहा बिना शराब जिनकी जान जोखिम में आ जाएगी उनको परमिट जारी करिए।

सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना सरकार के अन्याय का एक और प्रमाण- गुप्ता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश की भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफलताओं का शर्मनाक रिकार्ड बनाती जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कुनीतियों और वादाखिलाफी ने हर वर्ग को त्रस्त और आंदोलित कर दिया है। श्री गुप्ता ने कहा कि अब प्रदेश की स्कूलों के 43 हजार सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना प्रदेश सरकार की नाकामी का ताजा प्रमाण है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्कूली बच्चों को स्कूलों में साफ सफाई करनी पड़ रही है! इन सफाई कर्मचारियों का मानदेय आज भी 2000 से 2400 रुपए ही है जबकि सत्ता संभालने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन कर्मचारियों को कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन साढ़े 4 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने इस वादेएस को पूरा नहीं किया। श्री गुप्ता ने कहा कि यह स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का खुला मखौल उड़ाना है। उन स्कूलों में, जहां बच्चे पढ़ाई करते हुए नवाचार सीखते हैं, गंदगी फैल रही है और बच्चों को सफाई करनी पड़ रही है।

निगरानी समिति की बैठक संपन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में जय भारत सत्याग्रह के सफल आयोजन के लिये गठित प्रदेश स्तरीय् निगरानी समिति की बैठक प्रभारी सत्यनारायण शर्मा की उपस्थिति मे संपन्न हुयी। इस बैठक में गुरूमुख सिंह होरा, रवि घोष, सुशील आनंद शुक्ला, राजेन्द्र तिवारी, सुमित्रा घृतलहरे, देवंचद्र मातलम उपस्थित हुये। कन्ट्रोल रूम प्रभारी कन्हैया अग्रवाल, महेन्द्र छाबड़ा, सलाम रिजवी उपस्थित हुये। इस बैठक में प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि सभी जिलों में पत्रकारवार्ता संपन्न हो चुकी है। मशाल जुलूस हो चुका है। सभी ब्लाकों मे पत्रकारवार्ता हो चुका है। 16 अप्रैल को जो कार्यक्रम जांजगीर-चांपा मे होना था। प्रियंका गांधी का आगमन बस्तर के लिये हो रहा है। इसलिये इस कार्यक्रम को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। नया कार्यक्रम संविधान जिंदाबाद रैली 1 सप्ताह बाद का जांजगीर- चांपा में प्रदेश स्तर के रैली का आयोजन होगा। इसके लिये हमारे समान विचारधारा के लोगो को आमंत्रित किया है। इसमें सहभागी हो सकते है। इसकी आज हमने समीक्षा की है। सबने अच्छा किया। एआईसीसी के दिशा निर्देश का पालन हुआ है।

कोरोना के बाद छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक रिकवरी अन्य राज्यों से बेहतर

- **स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जारी की असर 2022 की सर्वे रिपोर्ट**

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय से एनुवल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) - 2022 जारी करते हुए कहा कि कोरोना के वजह से विभिन्न राज्यों में बच्चों के सीखने के स्तर में काफी नुकसान हुआ वहीं छत्तीसगढ़ में 2021 की तुलना में 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षकों ने काफी मेहनत कर अपनी पूर्व स्थिति की ओर वापस आना शुरू किया। शीघ्र ही और बेहतर स्थिति में लाने की दिशा में विभाग एकजुट होकर कार्य करेंगा। असर द्वारा छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में 1679 गांव के 33 हजार 330 घरों तक पहुंचकर 3 से 16 आयु वर्ग के 64 हजार 131 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पूर्व प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय में नामांकन की जानकारी एकत्र की गई। 5-16 आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने, गणित और अंग्रेजी के कौशल को समझने के लिए जांच की गई।

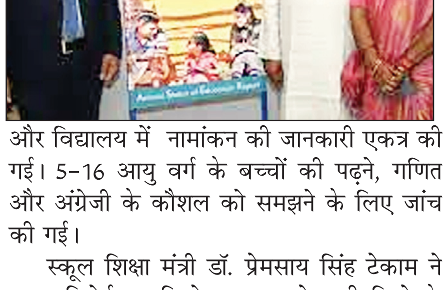

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने असर रिपोर्ट का विमोचन कर इसे सभी जिले के साथ साझा करते हुए इसके आधार पर जिलों में फॉलोअप एक्शन लेने की दिशा में कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा की जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में 'अंगना म शिक्षा कार्यक्रम' के माध्यम से माताओं को जोड़ा गया है। राज्य में इस वर्ष ग्रीष्मकाल में यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सीखने-सिखाने की जिम्मेदारी समुदायवार लेते हुए इसके स्तर को और ऊपर उठाने का कार्य किया जाएगा। अप्रैल माह के अंत तक समुदाय को इस कार्य के लिए तैयार कर उनका उन्मुखीकरण कर दो माह तक बच्चों को मूलभूत शिक्षा दी जाएगी।

मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री जतन योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों में मरम्मत का कार्य किया जाएगा, ताकि नये सत्र में बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए आकर्षक वातावरण मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप बालवाड़ी खोले जाने और स्थानीय भाषा में पढ़ाई में सहयोग देने के कारण पढ़ाई के स्तर में सुधार हुआ है। स्थानीय भाषा में कार्य करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को बहुभाषा शिक्षा पर ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए भाषाई सर्वे के आधार पर सुधारात्मक कार्य करने की दिशा में पहल की गई है। बस्तर के 200 स्कूलों में इस परियोजना के अंतर्गत आगे का काम शुरू हो गया है। पहला सर्वे असर छत्तीसगढ़ - 2021 अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया गया जब महामारी के कारण कई महीने बंद रहने के बाद स्कूल फिर से खुले ही थे। इस रिपोर्ट में स्कूल बंद होने के कारण हुए लिर्निंग लॉस पर महत्वपूर्ण अनुमान दिये। असर छत्तीसगढ़ - 2022 लगभग एक साल की 'कैंच-अप' गतिविधियों के बाद बच्चों की स्कूली शिक्षा और बुनियादी क्षमता की स्थिति को समझने के लिए नवंबर 2022 में लौटा। इसके साक्ष्य यह समझने में मदद कर सकते हैं कि लर्निंग रिकवरी अब तक कितनी सफल रही है और आगे बढ़ने के लिए किस तरह की मदद की आवश्यकता होगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.